

[2023] 7 एस. सी. आर 772

ऑरेलियानो फर्नांडीस

वी.

गोवा राज्य और अन्य

(2014 की सिविल अपील संख्या 2482)

12 मई, 2023

[ए. एस. बोपन्ना और हिमा कोहली, जे. जे.]

केंद्रीय सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील)

नियम, 1965 आर। 11 (IX), r. 14 (2) - केंद्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1964 आर। 3 सी-कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न का आरोप

- प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों की अवहेलना-अपीलार्थी को प्रतिवादी नं. 2 - गोवा विश्वविद्यालय-अपीलार्थी पर कई छात्राओं द्वारा यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया गया था-अपीलार्थी को सेवा प्रदान की गई थी

उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों की जांच के लिए स्पष्टीकरण देने के लिए नोटिस के साथ

इसके बाद मई 2009 के महीने में कार्यवाही हुई, जब

12 सुनवाई, जिनमें से अधिकांश एक के बाद एक, समिति द्वारा आयोजित की गई थी-अपीलार्थी स्वास्थ्य कारणों से उपस्थित होने में असमर्थ था, हालाँकि, उसने समय बढ़ाने की मांग की थी, जिसे अस्वीकार कर दिया गया था -

कार्यवाही एक तरफ से आगे बढ़ी और अपीलार्थी द्वारा यौन उत्पीड़न की पुष्टि करते हुए अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की-समिति ने उन्हें सेवा से बर्खास्त करने की सिफारिश की-कार्यकारी परिषद (ईसी) ने स्वीकार कर लिया

समिति और अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया था-ईसी ने संचालन करने का प्रस्ताव रखा सी. सी. एस. (सी. सी. ए.) नियमों के नियम 14 के तहत उसके खिलाफ एक जांच-हालाँकि, अपीलार्थी को सूचित किया गया कि मेधा कोतवाल के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित एक आदेश के आलोक में, महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम के लिए शिकायत समिति की रिपोर्ट

कार्यस्थल को सी. सी. एस. (सी. सी. ए.) नियमों के तहत एक जांच रिपोर्ट माना जाएगा जो अनुशासनात्मक प्राधिकरण के लिए बाध्यकारी होगा।

सरकारी कर्मचारी अनुशासन प्राधिकरण के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाई शुरू करने के लिए अपीलार्थी को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया

अपीलार्थी ने उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका दायर की, जिसे खारिज कर दिया गया-अपील पर अभिनिर्धारित किया गया: यह एक स्वीकृत स्थिति है कि जांच की कार्यवाही को प्रारंभिक चरण में ही समाप्त कर दिया गया था और यह

यदि समिति की रिपोर्ट पहले प्रस्तुत की गई थी, जिस पर निर्वाचन आयोग द्वारा कार्रवाई की गई थी-समिति स्वयं अपनी जांच के दायरे के बारे में स्पष्ट नहीं थी, अपीलार्थी को शरण देने के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता है

यह धारणा कि समिति का प्रेषण तथ्य तक ही सीमित था

772 ऑरिलियानो फर्नांडीस बनाम। गोवा राज्य और अन्य

अकेले खोज और यह एक अनुशासनात्मक समिति के कार्यों का निर्वहन नहीं कर रहा था, जैसा कि सेवा नियमों के तहत विचार किया गया था -

यह भी उल्लेखनीय है कि जांच को समाप्त करने के लिए सी. सी. एस. (सी. सी. ए.) नियमों के तहत निर्धारित समय अवधि आम तौर पर एक अवधि के भीतर होती है।

नियुक्ति के आदेश की प्राप्ति की तारीख से छह महीने तत्काल मामले में, पूरी प्रक्रिया को फ्लैट 39 में लपेटा गया था

दिन-यह समिति की जल्दबाजी को दर्शाता है।

अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करें-जांच को बंद करने के लिए समिति द्वारा दिखाई गई अनुचित जल्दबाजी, अपीलार्थी के निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार में कटौती को उचित नहीं ठहरा सकती है-जब लिए गए निर्णय की वैधता प्रक्रिया की निष्पक्षता पर निर्भर है और

अपनाई गई प्रक्रिया ही संदिग्ध हो गई, फिर निर्णय

न्यायिक जांच का सामना नहीं कर सकता है और इसके लिए व्यापक रूप से खुला है

हस्तक्षेप-संचालन के लिए समिति में निहित विवेकाधिकार

प्राकृतिक न्याय-इसके परिणामस्वरूप, विवादित निर्णय सेवाओं को समाप्त करने के निर्वाचन आयोग द्वारा लिए गए निर्णय को बरकरार रखना

अपीलकर्ता का, अपीलीय प्राधिकरण द्वारा विधिवत समर्थन नहीं किया जा सकता है

टिके रहें।

भारत का संविधान-कला। 309- सेवा की शर्तें

कार्यक्षेत्र-कला। 309 स्वयं भर्ती के लिए प्रावधान नहीं करता है या सरकारी कर्मचारियों की सेवा की शर्तें, लेकिन यह शक्ति प्रदान करती हैं

कानून बनाने के लिए उपयुक्त विधायिका और राष्ट्रपति पर और इन मामलों से संबंधित नियम बनाने के लिए किसी राज्य की सरकार

तथापि, कोई भी अधिनियम या नियम जो गारंटीकृत अधिकारों का उल्लंघन करता है

अनुच्छेद 311 के तहत सरकारी कर्मचारी अमान्य होगा-इसी तरह, इस तरह के एक अधिनियम या नियम को अमान्य माना जाएगा यदि यह संविधान के भाग III के तहत गारंटीकृत किसी भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है।

भारत का संविधान-कला। 310 - आनंद का सिद्धांत

अनुच्छेद 310 "आनंद के सिद्धांत" का प्रतीक है और सरकारी कर्मचारियों के संदर्भ में, उनकी सेवा के कार्यकाल से संबंधित है।

एक बार नियुक्त होने पर सरकारी कर्मचारियों का मूल संविदात्मक हो सकता है।
कार्यालय के लिए, वे एक दर्जा और अपने अधिकार प्राप्त करते हैं और

डाक या

दायित्व अब दोनों की सहमति से निर्धारित नहीं होते हैं

पक्षकार, लेकिन कानून या सांविधिक नियमों द्वारा शासित होते हैं।

भारत का संविधान-कला। . 311 311 - -

का प्रकटीकरण

प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत-सुरक्षा की भावना प्रदान करना
संविधान निर्माताओं के पास [2023] 7 एस. सी. आर. हैं।

सरकारी कर्मचारियों के कार्यकाल में,

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

अनुच्छेद 311 के खंड (1) और (2) में दिए गए दंड या बर्खास्तगी या हटाने या उनके पद में कमी के संबंध में सुरक्षा उपायों को शामिल किया गया है-साथ ही, उसी सार्वजनिक हित और सार्वजनिक भलाई के प्रति सचेत रहना जो इसकी अनुमति नहीं देता है।

भ्रष्ट, बेईमान या अक्षम पाए जाने वाले सरकारी कर्मचारियों को सेवा में बनाए रखा जाए, अनुच्छेद 311 के खंड (2) के दूसरे परंतुक के तहत एक उपाय प्रदान किया जाता है, जिसके तहत उनकी सेवाओं को अनुशासनात्मक जांच किए बिना समाप्त किया जा सकता है।

भारत का संविधान-Art.14-प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का एक आधार-प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत जो इसमें परिलक्षित होते हैं

अनुच्छेद 311, एक खाली मंत्र नहीं है-वे अनुच्छेद 14 की आधारशिला हैं और इन सिद्धांतों का कोई भी उल्लंघन है।

संविधान के अनुच्छेद 14 के उल्लंघन के समान-एक लोक सेवक को प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों से इनकार करने से इस आधार पर लिए गए निर्णय को अमान्य कर दिया जा सकता है कि यह मनमानेपन की बुराई से प्रभावित होता है और इसके परिणामस्वरूप एक लोक सेवक को समान सुरक्षा से वंचित कर दिया जाएगा।

कानून से।

सिद्धांत/सिद्धांत-प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत-जुड़वां आधार: नेमो जूडेक्स इन कौसा सुआ और ऑडी अल्टेरम पार्टेम-जुड़वां एंकर जिन पर प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत न्यायिक प्रक्रिया में निर्भर करते हैं, चाहे वे अर्ध-न्यायिक या प्रशासनिक प्रकृति के हों।

नेमो जूडेक्स कौसा सुआ में हैं, अर्थात्, कोई भी व्यक्ति अपने स्वयं के मामले में न्यायाधीश नहीं होगा क्योंकि न्याय न केवल किया जाना चाहिए, बल्कि स्पष्ट रूप से किया जाता देखा जाना चाहिए और ऑडी अल्टेरम पार्टेम, अर्थात् न्यायिक, अर्ध-न्यायिक या प्रशासनिक कार्यवाई से प्रभावित व्यक्ति को होना चाहिए

कोई भी निर्णय लेने से पहले सुनवाई का अवसर दिया जाता है।

न्याय प्रशासन में निष्पक्ष कार्यवाई और निष्पक्षता

सेवा न्यायशास्त्र-न्यायालय प्राकृतिक न्याय के उपरोक्त सिद्धांतों के साथ समन्वय में वैधानिक प्रावधानों की व्याख्या इस आधार पर करते हैं कि कोई भी वैधानिक प्राधिकरण निहित मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं करेगा।

संविधान में-इसके अलावा जब उन अधिकारियों की बात आती है जिनसे न्यायिक और अर्ध-न्यायिक कार्यों का निर्वहन करने की अपेक्षा की जाती है, तो ऑडी अल्टेरम पार्टेम का नियम समान बल के साथ लागू होता है-तर्कसंगतता प्रक्रियात्मक मामलों में जीवन को प्रभावित करती है, चाहे वह नोटिस के तत्व हों, नोटिस की सामग्री हो, जांच का दायरा हो, उपलब्ध सामग्री हो या ऐसी सामग्री का खंडन करने का पर्याप्त अवसर हो और यह सब

किसी भी स्तर पर न्याय की विफलता से बचने के लिए।

ऑरिलियानो फर्नांडीस बनाम। गोवा राज्य और अन्य

केंद्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1965-आर। 14 - अभिव्यक्ति "जहाँ तक व्यवहार्य है"- "जहाँ तक व्यवहार्य है" अभिव्यक्ति का उपयोग प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों से समझौता किए बिना, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न जैसे संवेदनशील मामले में जांच करने के लिए एक निष्पक्ष प्रक्रिया को अपनाने के लिए शिकायत समिति के लिए उपलब्ध जोड़ों में एक खेल का संकेत देता है। न्याय का प्रशासन-सेवा मामले में प्रक्रियात्मक व्यवस्था में तर्कसंगतता-मुख्य सिद्धांत

यह ध्यान में रखना आवश्यक है कि दुराचार के आरोपी व्यक्ति को मामले के बारे में सूचित किया जाना चाहिए, उसके समर्थन में साक्ष्य प्रदान किया जाना चाहिए और कोई भी प्रतिकूल निर्णय लेने से पहले अपना पक्ष प्रस्तुत करने का एक उचित अवसर दिया जाना चाहिए-इसी तरह, संबंधित नियोक्ता से भी निष्पक्ष रूप से कार्य करने और एक ऐसी प्रक्रिया अपनाने की उम्मीद की जाती है जो न्यायपूर्ण, निष्पक्ष और उचित हो-पूरा उद्देश्य प्रक्रियात्मक व्यवस्था में तर्कसंगतता की सांस लेना है, लेकिन, तर्कसंगतता की परीक्षा अमूर्त नहीं हो सकती है-इसे व्यावहारिक और मामले के तथ्यों और परिस्थितियों की वास्तविकताओं में आधारित होना चाहिए।

कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013-उस वादे को पूरा करने के लिए जो पाँच अधिनियम पूरे देश में कामकाजी महिलाओं के लिए रखता है

उचित निर्देश जारी किए गए।

अपील की अनुमति देते हुए और निर्देश जारी करते हुए, न्यायालय

पकड़ना: 1. अपीलार्थी की याचिका कि समिति ने अपनी जांच के प्रेषण को 'तथ्य-खोज कार्यवाही' के रूप में समझा,

अपीलार्थी को संबोधित 17 मार्च 2009 और 20 अप्रैल 2009 के पत्रों की सामग्री से इसका पता लगाया जा सकता है। समिति द्वारा यह धारणा कि विश्वविद्यालय को केवल एक तथ्य-खोज रिपोर्ट प्रस्तुत करने की आवश्यकता थी, निर्वाचन आयोग के लिए कोई अलग नहीं थी, जैसा कि निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष द्वारा 8 सितंबर 2009 को जारी ज्ञापन के अवलोकन से पता चलता है, जिन्होंने समिति की रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद, अपीलार्थी को सूचित किया कि उनके खिलाफ सी. सी. एस. (सी. सी. ए.) नियमों के नियम 14 के तहत एक जांच करने का प्रस्ताव था। यह पहली बार था जब प्रत्यर्थियों ने अपीलार्थी को सूचित किया कि निर्वाचन आयोग ने आरोप के अनुच्छेदों का विवरण तैयार करने, आरोप के प्रत्येक अनुच्छेदों और अन्य दस्तावेजों के समर्थन में कदाचार के आरोप लगाने के नियमों के तहत निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने का फैसला किया था और उसके पास [2023] 7 एस. सी. आर. थे।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

अपीलार्थी ने जवाब प्रस्तुत किया। लेकिन यह एक स्वीकृत स्थिति है कि उक्त जांच कार्यवाही को प्रारंभिक चरण में ही निरस्त कर दिया गया था और यह पहले प्रस्तुत की गई समिति की रिपोर्ट थी, जिस पर चुनाव आयोग ने 28 जनवरी 2010 को लिए गए निर्णय के संदर्भ में कार्रवाई की थी। जब समिति स्वयं इस बारे में स्पष्ट नहीं थी कि इसकी जांच के दायरे में, अपीलार्थी को शरण देने के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता है

एक धारणा कि समिति का प्रेषण केवल तथ्य खोजने तक ही सीमित था और यह एक अनुशासनात्मक समिति के कार्यों का निर्वहन नहीं कर रहा था, जैसा कि सेवा नियमों के तहत विचार किया गया था।

[पैरा 61] [817-ई-एच; 818-ए]

2. यह भी उल्लेखनीय है कि जांच को समाप्त करने के लिए सी. सी. एस. (सी. सी. ए.) नियमों के तहत निर्धारित समय अवधि आम तौर पर इसके भीतर होती है।

नियुक्ति के आदेश की प्राप्ति की तारीख से छह महीने की अवधि। लेकिन, यहाँ, पूरी प्रक्रिया को 39 दिनों में पूरा कर लिया गया। यह समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने की तीव्र जल्दबाजी को दर्शाता है। कार्यवाही को समाप्त करने के लिए अत्यधिक चिंता का एक ऐसा ही स्पष्ट उदाहरण पत्र से स्पष्ट है दिनांक 5 मई 2009, समिति द्वारा अपीलार्थी को संबोधित करते हुए उसे सूचित किया गया कि उसका जवाब दाखिल करने की अगली तारीख और

समिति को इस तथ्य से एकत्र किया जा सकता है कि 20 मई 2009 को समिति ने अपीलार्थी को अंतिम आदेश देते हुए लिखा था। 20 मई 2009 को खुद को पेश करने का अवसर, न केवल अपने बयान को पूरा करने के लिए, बल्कि शिकायतकर्ताओं और अन्य गवाहों से जिरह करने के लिए भी। इसके साथ ही समिति ने अपीलार्थी को छह और बयान भेजे और उन्हें 48 घंटे के भीतर यानी 22 मई, 2009 तक अपना जवाब देने का निर्देश दिया। [पैरा 63] [818-ई-एच; 819-ए]

3. जांच को बंद करने के लिए समिति द्वारा दिखाई गई अनुचित जल्दबाजी, ऑरिलियानो फर्नांडीस बनाम में कटौती को उचित नहीं ठहरा सकती है।

गोवा राज्य और अन्य

अपीलार्थी का निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार। उचित प्रक्रिया, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का एक महत्वपूर्ण पहलू, समिति द्वारा जांच कार्यवाही के संचालन के कार्य के तरीके के कारण गंभीर रूप से समझौता किया गया था। जैसा कि उल्लेख किया गया है।

ऊपर, जब वर्तमान अपील की कार्यवाही, विषय वस्तु हुई थी, तो पी. ओ. एस. एच. अधिनियम कहीं भी क्षितिज पर नहीं था और क्षेत्र पर विशाखा दिशानिर्देशों का कब्जा था। उक्त दिशानिर्देशों में प्रक्रियात्मक अनुपालन करने में प्राकृतिक न्याय और निष्पक्षता के सिद्धांतों के अनुप्रयोग को भी शामिल नहीं किया गया है। इस पहलू पर दिशा-निर्देशों में मौन समिति को प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों को दरकिनार करने और अपीलार्थी को निष्पक्ष सुनवाई देने के उचित अवसर को कम करने के लिए एक नियंत्रण नहीं दे सकता था। इस न्यायालय ने बार-बार कहा है कि जब नियम मौन हैं, तब भी उनमें प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों को पढ़ा जाना चाहिए। पीड़ितों/शिकायतकर्ताओं के प्रति निष्पक्ष होने और शिकायतों को शीघ्रता से समाप्त करने की अपनी गहरी चिंता में, समिति ने अपीलार्थी के साथ घोर अन्याय किया है।

इसने इस मूल सिद्धांत की पूरी तरह से अनदेखी की है कि न्याय न केवल किया जाना चाहिए, बल्कि स्पष्ट रूप से किया जाता देखा जाना चाहिए। ऑडी अल्टरम पार्टेम के सिद्धांतों को इस तरह से हवा में नहीं फेंका जा सकता था। [पैरा 65] [819-डी-जी]

4. जब नियोक्ता स्वयं समिति के प्रेषण से अनजान था और समिति अपनी कार्यवाही को तथ्य-निष्कर्ष के रूप में वर्णित करते हुए उसी धारणा के तहत बनी रही। इस प्रकार, उत्तरदाताओं के लिए यह और भी अधिक अनिवार्य था कि वे प्रथम समिति की रिपोर्ट प्राप्त करने पर रुकें और अगला कदम उठाने से पहले कानूनी स्थिति का सत्यापन करें। इन सब में आगे-पीछे, यह नियम 14 के तहत निर्धारित प्रक्रिया थी

कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की जांच करना जिसका शीघ्र निपटान में त्याग किया गया था, जिसे न तो उचित ठहराया जा सकता है और न ही स्वीकार किया जा सकता है। सी. सी. एस. (सी. सी. ए.) नियमों के नियम 14 (2) और सी. सी. एस. (आचरण) नियमों के नियम 3 सी में अंतःस्थापित परंतुक का आशय और उद्देश्य यह है कि यौन उत्पीड़न की शिकायत की जांच करने के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया, जिससे नियमों के तहत एक बड़ा जुर्माना लगाया जा सकता है, निष्पक्ष, निष्पक्ष और नियमों के अनुरूप होनी चाहिए। उल्लेखनीय है कि शिकायत समिति द्वारा की गई जांच के दौरान प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करने पर जोर देने का बाद में अधिनियमित [2023] 7 एस. सी. आर. के नियम 7 (4) में विशिष्ट उल्लेख मिलता है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

2013 के नियम। लेकिन कानून या नियमों के अभाव में भी उचित प्रक्रिया के पीछे की भावना को कभी दबाया या नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था क्योंकि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत निर्णय लेने की प्रक्रिया का सार हैं और इन्हें प्रत्येक न्यायिक या अर्ध-न्यायिक कार्यवाही में भी पढ़ा जाना चाहिए। [पारस 67,68] [820-डी-जी]

5. यह कहने का मतलब यह नहीं है कि समिति से यह अपेक्षा की जाती थी कि भले ही उसे एक जांच प्राधिकरण के रूप में वर्णित किया गया हो, मेधा कोतवाल के मामले में निर्णय के आधार पर और नियम 14 के तहत निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने की आवश्यकता होती है, वह जांच का संचालन इस तरह करेगी जैसे कि यह एक पूर्ण-स्तरीय परीक्षण हो। नियम 14 (2) के परंतुक में प्रयुक्त अभिव्यक्ति, 'जहाँ तक व्यावहारिक हो', को व्यावहारिक तरीके से पढ़ना और समझना होगा। अनुशासनात्मक प्राधिकरण द्वारा शुरू की गई ऐसी किसी भी कार्यवाही में, यौन उत्पीड़न की पीड़ित और अपराधी के अधिकारों के बीच एक संतुलित संतुलन बनाना होगा।

कर्मचारी। साथ ही, दोनों पक्षों के हित में प्रक्रिया में निष्पक्षता को अनिवार्य रूप से अपनाना होगा। आखिरकार, हंस के लिए जो चटनी है, वह गैंडर के लिए चटनी है। [पैरा 69] [820-एच; 821-ए-बी]

6. वास्तव में, जांच की कार्यवाही में स्पष्ट दोष और प्रक्रियात्मक खामियां उसके बाद ही महीने में हुईं।

मई, 2009 में, जब 12 सुनवाई, जिनमें से अधिकांश एक के बाद एक, समिति द्वारा तेज गति से आयोजित की गई थी। एक पर

दूसरी ओर, समिति अपीलार्थी को आगे बढ़ाती रही, कुछ और शिकायतकर्ताओं और अन्य गवाहों के बयान बाद में प्राप्त हुए और उनसे अपना जवाब प्रस्तुत करने के लिए कहा और दूसरी ओर, उसने उसे निर्देश दिया कि वह एक सप्ताह की अवधि में उक्त शिकायतकर्ताओं और गवाहों से जिरह करने के साथ-साथ अपनी आगे की गवाही भी दर्ज करने के लिए तैयार हो। भले ही अपीलार्थी द्वारा लिए गए चिकित्सा आधार संदिग्ध लगे, समिति को उसे अपना बचाव तैयार करने के लिए उचित समय देना चाहिए था, विशेष रूप से तब जब एक वकील के माध्यम से प्रतिनिधित्व करने के उसके अनुरोध को पहले ही अस्वीकार कर दिया गया था। यह सारी अनुचित चिंता ही थी जिसके कारण समिति द्वारा की गई जांच की कार्यवाही को शॉर्ट-सर्किट कर दिया गया था और प्रक्रिया की निष्पक्षता को नुकसान पहुंचा था। [पैरा

71] [821 - ई-एच]

7. उपरोक्त कारणों से, प्रक्रिया और उसके परिणाम पर सवाल उठाने के लिए अपीलार्थी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। कोई शक नहीं है। कि इस तरह के मामले संवेदनशील हैं और उन्हें सावधानी से संभाला जाना चाहिए। उत्तरदाताओं को सत्रह ऑरेलियानो फनडिस बनाम प्राप्त हुए थे।

गोवा राज्य और अन्य

यौन शोषण के गंभीर आरोप लगाने वाली छात्रों की शिकायतें

अपीलार्थी के खिलाफ उत्पीड़न। लेकिन यह जांच की प्रक्रियात्मक निष्पक्षता को पूरी तरह से स्वीकार करने का आधार नहीं होगा, विशेष रूप से जब जांच से बड़ी दंडात्मक कार्यवाही लागू हो सकती है। जब लिए गए निर्णय की वैधता प्रक्रिया की निष्पक्षता पर निर्भर होती है और अपनाई गई प्रक्रिया ही संदिग्ध हो जाती है, तो निर्णय न्यायिक जांच का सामना नहीं कर सकता है और हस्तक्षेप के लिए व्यापक रूप से खुला है। यह बिना किसी कारण के नहीं कहा जाता है कि केवल एक निष्पक्ष प्रक्रिया ही उचित परिणाम की गारंटी दे सकती है। इस मामले में, यौन उत्पीड़न के पीड़ितों के प्रति निष्पक्ष होने की समिति की चिंता ने उन्हें अधिक नुकसान पहुंचाया है। [पैरा 72] [822-ए-सी]

8. अतः इस न्यायालय की राय है कि समिति द्वारा संचालित कार्यवाहियां

मई, 2009 का महीना संबंधित नियमों में निर्धारित "जहां तक संभव हो" मानदंड से कम हो गया। में निहित विवेकाधिकार प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों की अवहेलना करते हुए जांच करने के लिए समिति का अनुचित तरीके से प्रयोग किया गया है। इसके परिणामस्वरूप, अपीलीय प्राधिकरण द्वारा विधिवत समर्थित अपीलार्थी की सेवाओं को समाप्त करने के निर्वाचन आयोग द्वारा लिए गए निर्णय को बरकरार रखने वाले विवादित निर्णय को कायम नहीं रखा जा सकता है और तदनुसार रद्द कर दिया जाता है और निम्नलिखित निर्देशों के साथ अलग कर दिया जाता है: (i) मामले को जांच की कार्यवाही शुरू करने के लिए शिकायत समिति को वापस भेज दिया जाता है, जैसा कि वे 5 मई 2009 को थे; (ii) समिति अपीलार्थी को अपना बचाव करने के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान करेगी; (iii) अपीलार्थी कार्यवाही के किसी भी स्थगन की मांग नहीं करेगा; (iv) समिति द्वारा उचित आदेशों के लिए अनुशासनात्मक प्राधिकरण को एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी; (v) लंबे समय के बीतने को ध्यान में रखते हुए, प्रत्यर्थियों को समिति द्वारा निर्धारित सुनवाई की पहली तारीख से तीन महीने के भीतर पूरी प्रक्रिया को पूरा करने का निर्देश दिया जाता है; (vi) समिति और अनुशासनात्मक प्राधिकरण द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों द्वारा निर्देशित होगी; (vii) लागू किए गए नियम वैसे ही होंगे जैसे लागू थे।

समिति और अनुशासन प्राधिकरण विशुद्ध रूप से इस पर होंगे गुण और कानून के अनुसार; (ix) अपीलार्थी को [2023] 7 एस तक तत्काल बहाली या मजदूरी वापस करने का दावा करने का अधिकार नहीं होगा।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

आईरी पूरा हो गया है और अनुशासन द्वारा निर्णय लिया जाता है

ओरीटी। [पैरा 73] [822-डी-एच; 823-ए-बी]

मेनका गांधी बनाम। भारत संघ और एक अन्य (1978)

1 एस. सी. सी. 248 [1978] 2 एस. सी. आर. 621; रुस्तम कावासजी

कूपर वी। भारत संघ (1970) 1 एससीसी 248: [1970] 3

एस. सी. आर. 530; दिल्ली परिवहन निगम बनाम। डी टी सी।

मजदूर कांग्रेस और अन्य (1991) सप्लीमेंट (1) एससीसी 600 [1990] 1 सप्लीमेंट। एस. सी. आर. 142; भारत संघ और एक अन्य v. तुलसीराम पटेल (1985) 3 एससीसी 398: [1985] 2

पूरका एस. सी. आर. 131-अनुसरण किया गया।

मेधा कोतवाल लेल बनाम। भारत संघ (2013) 1 एस. सी. सी. 297 [2012] 9 एस. सी. आर. 895; हीरा नाथ मिश्रा और अन्य बनाम। प्राचार्य, राजेंद्र मेडिकल कॉलेज, रांची और

एक और (1973) 1 एससीसी 805; पी. डी. अग्रवाल बनाम भारतीय स्टेट बैंक और अन्य (2006) 8 एस. सी. सी. 776 [2006] 1 पूरका एस. सी. आर. 454; विशाखा और अन्य बनाम। राजस्थान राज्य

अन्य वी। भारत संघ और अन्य (1969) 2 एस. सी. सी. 262: [1970] 1 एससीआर 457; पुनः एच. के. (सभी शिशु) (1967) 1 सभी ईआर 226; मंगीलाल बनाम। एम. पी. राज्य (2004) 2 एस. सी. सी. 447 : [2004] 1 एस. सी. आर. 1; भारत संघ बनाम। कर्नल जे. एन. सिन्हा और एक अन्य (1970) 2 एस. सी. सी. 458: [1971] 1 एससीआर 791; स्वदेशी कॉटन मिल्स बनाम। भारत संघ (1981) 1 एस. सी. सी. 664 [1981] 2 एस. सी. आर. 533; मेधा कोतवाल लेल और अन्य बनाम। भारत संघ और अन्य (2013) 1 एस. सी. सी. 311; डॉ. विजयकुमारन सी. पी. वी. बनाम केरल केंद्रीय विश्वविद्यालय और अन्य, (2020) 12 एस. सी. सी. 426 [2020] 3 एस. सी. आर. 374-आश्रित

पर।

संदीप खुराना बनाम। दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड और अन्य आईएलआर

2006 (11) 1313; प्रोफेसर गिरिधर मद्रास बनाम। भारतीय विज्ञान संस्थान का प्रतिनिधित्व अध्यक्ष और अन्य (2019) एस. सी. सी. ऑनलाइन कर 3508; अविनाश मिश्रा बनाम। भारत संघ 2014 एस. सी. सी. ऑनलाइन डेल 1856-संदर्भित

को।

ऑरिलियानो फर्नांडीस बनाम। राज्य और अन्य

मामला कानून संदर्भ

[2012] 9 एससीआर 895

उस पर भरोसा करें

पै

रा 15

[1985] 2 पूरक। एससीआर 131

पीछा किया।

पै

रा 21

(1973) 1 एस. सी. सी. 805

उस पर भरोसा करें

पै

रा 25

[2006] 1 पूरक। एससीआर 454

उस पर भरोसा करें

पै

रा 25

[1997] 3 पूरक। एससीआर 404

पै

रा 26

उस पर भरोसा करें

[1978] 2 एससीआर 621

पै

रा 37

पीछा किया।

[1970] 3 एससीआर 530

पीछा किया।

रा 38

(1950) एससीसी 228

उस पर भरोसा करें

पै

रा 38

[1990] 1 पूरक। एस. सी. आर. 142

पीछा किया।

पै

रा 39

[1970] 1 एससीआर 457

उस पर भरोसा करें

पै

रा 41

[2004] 1 एससीआर 1

उस पर भरोसा करें

पै

रा 42

[1971] 1 एससीआर 791

उस पर भरोसा करें

पै

रा 43

[1981] 2 एससीआर 533

उस पर भरोसा करें

पै

रा 44

(2013) 1 एस. सी. सी. 311

उस पर भरोसा करें

पै

पै

रा 49

[2020] 3 एससीआर 374

उस पर भरोसा करें

पै

रा 57

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णय: सिविल अपील सं. 2

2014 से।

उच्च न्यायालय के 15.03.2012 दिनांकित निर्णय और आदेश से

2011 के डब्ल्यू. पी. No.602 में पणजी में बॉम्बे बेंच में न्यायिक कार्य।

विश्वजीत भट्टाचार्य, वरिष्ठ अधिवक्ता। , अतुल झा, प्रज्ञान प्रा

शर्मा, सूर्य नारायण पात्रो, एन. बी. वी. श्रीनिवास रेड्डी, प्रियोन अंजन गोगोई, पी. वी. योगेश्वरन, अधिवक्ता। अपीलार्थी के लिए।

सुश्री रुचिरा गुप्ता, शिशिर देशपांडे, सुश्री उर्वी कपूर, डी।

नारायण सरकार, अधिवक्ता। उत्तरदाताओं के लिए।

न्यायालय का निम्नलिखित निर्णय दिया गया:

सूचकांक *

ए.

अपील का दायरा

घटनाओं का क्रम

बी.

1

एड। ध्यान दें: सूचकांक में पृष्ठांकन मूल निर्णय [2023] 7 एस. सी. ई. के अनुसार है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

(क) प्रथम से पहले की कार्यवाही

1-6

समिति

कार्यपालिका के समक्ष कार्यवाही

(ख)

परिषद

6-8

अनुशासनात्मक प्राधिकरण का निर्णय

सी.

8-9

और अपीलीय प्राधिकरण

9-10

उच्च न्यायालय का निर्णय

डी.

ई.

के लिए वकील द्वारा प्रस्तुत तर्क

पार्टियाँ

10

-16

अपीलार्थी के लिए वकील

(अ)

10-12

उत्तरदाताओं के लिए वकील	
(ख)	12-16
नंबर 2 और 3	
ट्रायड: अनुच्छेद 309,310 और 311	
एफ.	16
-19	
भारत के संविधान का	
(अ)	
अनुच्छेद 309: सेवा की शर्तें	17
(ख) अनुच्छेद 310: आनंद का सिद्धांत	18
(ग)	
अनुच्छेद 311: की एक अभिव्यक्ति	
प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत	19
अनुच्छेद 14: के सिद्धांतों का आधार	
जी.	
प्राकृतिक न्याय	2
0-21	
एच. द ट्विन एंकर: कारण में निमो जूडेक्स	
सुआ और ऑडी अल्टेरेम पार्टेम	

-26	सेवा में निष्पक्ष कार्रवाई और निष्पक्षता आई. न्यायशास्त्र	21
-29	वैधानिक व्यवस्था जे.	26
-31	(क) गोवा विश्वविद्यालय संविधि (ख) सीसीएस (सीसीए) नियम ए. एन. ओ. फर्नण्डेस का व्यावहारिक अनुप्रयोग V. (ग)	29 29-30

गोवा राज्य और अन्य

" जहाँ तक व्यावहारिक है नियम 30-31

'विशाखा' मामले से पौंश तक की यात्रा

31-38

अधिनियम

विशाखा दिशानिर्देश: भरते हुए

(अ)

31-33

वैक्यूम

मेधा कोतवाल लेलेक मामला: फॉलोअप लें

(ख)

निरंतर मंदस के माध्यम से

33-36

पौंश अधिनियम का अधिनियमन और

(ग)

नियम

36-37

सांस लेने में तर्कसंगतता

(घ)

प्रक्रियात्मक व्यवस्था

37-38

विश्लेषण और चर्चा

38-49

(ए) उच्च द्वारा हस्तक्षेप का दायरा

न्यायिक समीक्षा में न्यायालय

	39-40
(ख)	
जहाँ तक "के पालन का विस्तार	
व्यावहारिक "मानक	
	40-42
समिति की अपनी समझ	
((ग)	
आदेश	
	42-44
((घ)	
बवंडर कार्यवाही	
	44-47
(ई)	
कार्यकारी परिषद ने क्या किया?	
	47-49
फाल्टर?	
निष्कर्ष	
	49-52
उपसंहार	
	53-55
दिशा-निर्देश	
	55-59

ए कोहली, जे।

आवेदन की प्रतिलिपि

अपीलार्थी द्वारा निर्णय को चुनौती दी गई है

मार्च, 2012, न्यायिक उच्च न्यायालय [2023] 7 एस. सी. आर. द्वारा पारित।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

गोवा में बॉम्बे बेंच ने कार्यस्थलों पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम के लिए स्थायी समिति की रिपोर्ट को स्वीकार करते हुए गोवा विश्वविद्यालय (अनुशासनात्मक प्राधिकरण) की कार्यकारी परिषद 3 द्वारा पारित आदेश 2 के खिलाफ उनके द्वारा दायर एक रिट याचिका को खारिज कर दिया।

केंद्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1965 के नियम 11 (IX) के तहत सेवाओं से बर्खास्तगी और भविष्य के रोजगार से अयोग्यता का एक बड़ा जुर्माना, जिसे राज्यपाल और गोवा विश्वविद्यालय के कुलाधिपति द्वारा विधिवत बरकरार रखा गया था।

प्राधिकरण '।

B. घटनाओं का अनुक्रम

(क) पहली समिति से पहले की प्रक्रियाएँ:

2. मामले के तथ्यात्मक मैट्रिक्स को कालानुक्रमिक अनुक्रम में रखा जाना चाहिए। अपीलार्थी ने अपने कार्यकाल की शुरुआत में

उत्तरदाता नं. 2 - गोवा विश्वविद्यालय में एक अस्थायी व्याख्याता के रूप में

वर्ष 1996 में राजनीति विज्ञान विभाग। उन्हें वर्ष 2003 में उक्त विभाग का प्रमुख नियुक्त किया गया था। यह अपीलार्थी का बयान है, जिसका दूसरे पक्ष ने पुरजोर खंडन किया है, जो उनके खिलाफ राजनीति विज्ञान विभाग की विभागीय परिषद द्वारा एक प्रस्ताव पारित किए जाने से व्यथित है, दो छात्राओं ने अपने दोस्तों के साथ प्रतिवादी नं. 2 - विश्वविद्यालय, उसके हाथों शारीरिक उत्पीड़न का आरोप लगाता है। उक्त शिकायतें प्रारंभिक बिंदु थीं

प्रत्यर्थी सं. के पंजीयक द्वारा शिकायतें प्राप्त करने पर समिति द्वारा शुरू की गई जांच। 2 - विश्वविद्यालय। समिति ने अपीलार्थी को एक नोटिस दिया जिसमें उसे नौ शिकायतों में उसके खिलाफ लगाए गए आरोपों की व्याख्या करने और 24 अप्रैल, 2009 को व्यक्तिगत सुनवाई के लिए उसके सामने पेश होने के लिए कहा गया, एक तारीख जिसे बाद में बदलकर 27 अप्रैल, 2009 कर दिया गया। समकालीन रूप से, प्रत्यर्थी का पंजीयक सं. 2 - विश्वविद्यालय ने अपीलार्थी को आरोप सौंपने और जांच के समापन तक छुट्टी पर जाने का निर्देश दिया।

2011 का 1 डब्ल्यू. पी. सं. 602

2 तिथि 10 मई, 2010

3 संक्षेप में 'ईसी'

4 तिथि 05 जून, 2009

5 संक्षेप में 'समिति' 6 संक्षेप में सी. सी. एस. (सी. सी. ए.) नियम 7 19 अप्रैल, 2011 के आदेश के माध्यम से 8 शिकायत दिनांक 11.03.2009 और 17.03.2009 9 दिनांक 08.04.2009 10 दिनांक 17 अप्रैल, 2009 के पत्र के आवरण के तहत ऑरिलियानो फर्नांडिस बनाम.

गोवा राज्य और अन्य [हिमा कोहली, जे.]

3. अपीलार्थी ने समिति को पचास-तीन पृष्ठों का विस्तृत जवाब दिया, जिसमें उन्होंने कुछ प्रारंभिक प्रश्न उठाए।

समिति द्वारा की जा रही जांच पर आपत्ति जताते हुए आरोप लगाया कि कुछ भटके हुए छात्रों द्वारा उनके खिलाफ एक सुव्यवस्थित साजिश रची गई थी।

संकाय के सदस्यों के साथ मिलीभगत और समिति द्वारा उन्हें भेजी गई छात्राओं की चौदह टिप्पणियों की सामग्री का खंडन किया। उन्होंने यह कहते हुए समापन किया कि उनके खिलाफ लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोप पूरी तरह से झूठे और निराधार थे। अपीलार्थी ने पक्षपात के आधार पर समिति के दो सदस्यों को हटाने की मांग करते हुए पंजीयक को एक पत्र भी संबोधित किया और इस दलील पर कि उनके अधीनस्थ होने के नाते, वे पक्षपात के लिए प्रवण थे।

4. समिति ने अपीलार्थी को 27 अप्रैल को सुनवाई के लिए बुलाया।

2009. अपीलार्थी द्वारा यह आरोप लगाया गया था कि उसके द्वारा नामित गवाह सहित सभी शिकायतकर्ताओं का बयान दर्ज किया गया था, जबकि उन्हें समिति कक्ष के बाहर इंतजार कराया गया। बाद में उन्हें बुलाया गया और समिति ने उनका बयान दर्ज किया। अगली सुनवाई में भी,

28 अप्रैल, 2009 को समिति द्वारा इसी तरह की प्रक्रिया को अपनाया गया था। 30 अप्रैल, 2009 को, अपीलार्थी को समिति से एक नोटिस प्राप्त हुआ जिसमें उसके खिलाफ प्राप्त यौन उत्पीड़न की एक और शिकायत शामिल थी, जिस पर उसे जवाब देने और 6 मई, 2009 को खुद को पेश करने का निर्देश दिया गया था। 2 मई 2009 के पत्र के माध्यम से, अपीलार्थी ने अतिरिक्त शिकायत का जवाब देने और शिकायत दर्ज करने की अनुमति देने के लिए और समय मांगा।

5. अपीलार्थी ने 8 मई, 2009 को नोटिस पर अपना जवाब प्रस्तुत किया। 6 मई, 2009 को एक वकील को नियुक्त करने के लिए अपीलार्थी का अनुरोध था समिति ने अस्वीकार कर दिया। उसी दिन, समिति द्वारा पहले के पत्र 1 1 के लिए एक शुद्धिपत्र जारी किया गया था जिसमें उन्हें सूचित किया गया था कि अगली तारीख

उनका जवाब दाखिल करने के लिए तय की गई तारीख को "12 जून, 2009" के बजाय "12 मई, 2009" के रूप में पढ़ा जाना चाहिए और आगे की गवाही की तारीख को "12 जून, 2009" के बजाय "14 मई, 2009" के रूप में पढ़ा जाना चाहिए।

6. 8 मई, 2009 के पत्र के माध्यम से, अपीलार्थी ने प्राप्त एक शिकायत पर समिति द्वारा की जा रही जांच पर आपत्ति जताई

प्रत्यर्थी सं. के पूर्व छात्र से। 2 - जमीन पर विश्वविद्यालय कि वह न तो छात्रा थी और न ही विश्वविद्यालय की कर्मचारी। इसके अतिरिक्त, उन्होंने बयान के बयान के अलावा उक्त शिकायत की एक प्रति मांगी, जो उन्हें पहले ही प्रस्तुत की जा चुकी थी।

1 1 तारीख 5 मई, 2009 12 27 अप्रैल, 2009 को हस्ताक्षर किए गए [2023] 7 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

7. 12 मई, 2009 को अपीलार्थी ने अपने खिलाफ लगाए गए कुछ आरोपों का खंडन करने के लिए एक गवाह का हलफनामा भेजा।

शिकायतकर्ता। सम तिथि के पत्र के माध्यम से, समिति ने संकाय के एक सदस्य डॉ. राहुल त्रिपाठी का एक अतिरिक्त बयान भेजा, जिन्होंने अपीलार्थी के खिलाफ शिकायतों को देखने के लिए गठित समिति से इस्तीफा दे दिया था और एक गवाह के रूप में गवाही दी थी।

8. अपीलार्थी ने 13 मई, 2009 को समिति को एक पत्र लिखकर इस याचिका पर उसके सामने पेश होने के लिए कुछ समय मांगा कि उसे पीठ में गंभीर दर्द के साथ अस्पताल में भर्ती कराया गया था। 14 मई, 2009 के नोटिस के माध्यम से समिति ने अपीलार्थी को अपना बयान दर्ज करने और अन्य शिकायतकर्ता के नए बयान पर अपना लिखित जवाब जमा करने के लिए 19 मई, 2009 को उसके समक्ष पेश होने का निर्देश दिया। हालाँकि, समिति ने अनुरोध के अनुसार समय बढ़ाने से इनकार कर दिया।

9. इस बीच, 13 मई, 2009 के पत्र के माध्यम से, अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी नं. 2 - स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की मांग कर रहा विश्वविद्यालय

स्वास्थ्य के आधार पर। हालाँकि, उक्त आवेदन उनके द्वारा 18 मई, 2009 को वापस ले लिया गया था। उसी तारीख को, अपीलार्थी के भाई द्वारा नियुक्त एक वकील ने उत्तरदाताओं को एक नोटिस जारी किया। 2 और 3 अपीलार्थी के समिति के समक्ष उपस्थित होने के लिए एक महीने का समय बढ़ाने की मांग करते हैं।

10. 20 मई, 2009 के अपने पत्र में समिति ने उल्लेख किया कि हालाँकि अपीलकर्ता अपनी आगे की गवाही दर्ज करने के लिए 19 मई, 2009 को उसके समक्ष पेश होने में विफल रहा था, लेकिन उसे अपनी गवाही पूरी करने और शिकायतकर्ताओं सहित गवाह से जिरह करने के लिए 23 मई, 2009 को खुद को पेश करने का एक अंतिम अवसर दिया जा रहा था। साथ ही, अपीलार्थी को छह और बयान भेजे गए, जिसमें 22 मई, 2009 तक उनका जवाब मांगा गया।

11. अपीलार्थी ने 23 मई, 2009 को कार्यवाही में भाग लेने में असमर्थता व्यक्त करते हुए समिति को एक और पत्र लिखा।

स्वास्थ्य के आधार पर और कार्यवाही को 3-4 सप्ताह के लिए स्थगित करने का अनुरोध किया। हालाँकि, उसी दिन समिति द्वारा उनके अनुरोध को अस्वीकार कर दिया गया था और अपीलार्थी को 23 मई, 2009 को उपस्थित रहने का निर्देश दिया गया था, जिसमें विफल रहने पर, उन्हें सूचित किया गया था कि समिति जांच के साथ आगे बढ़ेगी। समिति की कार्यवाहियों को स्थगित करने की मांग के लिए अपीलार्थी द्वारा किया गया दूसरा अनुरोध भी वैसा ही हुआ।

13 तिथि 22 मई, 2009

14 दिनांक 23 मई, 2009 ऑरेलियानो फर्नांडीस बनाम।

गोवा राज्य और अन्य [हिमा कोहली, जे.]

12. लगभग दस दिनों के बाद, अपीलार्थी ने समिति के अध्यक्ष को एक पत्र भेजा जिसमें अन्य बातों के साथ कहा गया था कि उसने आंशिक रूप से

अपनी बीमारी से उबर गए और पदच्युत करने की स्थिति में थे। उन्होंने नई तारीखों की मांग की ताकि वह उन्हें प्राप्त अतिरिक्त बयानों का जवाब दे सकें। हालाँकि, तब तक समिति अपीलार्थी के खिलाफ एकतरफा कार्रवाई कर चुकी थी और अपनी रिपोर्ट 16 प्रत्यर्थी सं. 2 - विश्वविद्यालय ने कहा कि उस जांच के संबंध में 18 बैठकें हुई थीं जिसने अपीलार्थी द्वारा शिकायतों के यौन उत्पीड़न को स्थापित किया था जो एक गंभीर अधिनियम था।

कदाचार और सी. सी. एस. आचरण नियमों के नियम 3 (1) (III) का घोर उल्लंघन था और परिणामस्वरूप, उनकी सेवाओं को समाप्त करने की सिफारिश की गई थी।

(ख) निष्पादन से पहले की प्रक्रियाएँ
परिषद

13. निर्वाचन आयोग ने 13 जून, 2009 को एक बैठक की जिसमें समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया गया और अपीलार्थी को पेश किया गया।

तत्काल प्रभाव से निलंबन के तहत। 8 सितंबर, 2009 के ज्ञापन के माध्यम से, निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष ने अपीलार्थी को सूचित किया कि निर्वाचन आयोग ने सीसीएस (सीसीए) नियमों के नियम 14 के तहत उनके खिलाफ जांच करने का प्रस्ताव रखा है। उक्त ज्ञापन के साथ आरोप के अनुच्छेदों का बयान, आरोप के प्रत्येक अनुच्छेदों के समर्थन में कदाचार के आरोप का बयान, दस्तावेजों की सूची और उक्त आरोपों को बनाए रखने के लिए गवाहों की एक सूची संलग्न थी। अपीलकर्ता को दिया गया था

अपने बचाव का एक लिखित बयान प्रस्तुत करने और यह बताने के लिए कि क्या वह व्यक्तिगत रूप से सुनना चाहते हैं, दस दिनों का समय।

14. अपीलार्थी ने उपरोक्त ज्ञापन का बीस पृष्ठों में विस्तृत जवाब प्रस्तुत किया और यौन उत्पीड़न की शिकायतों से संबंधित कई दस्तावेजों और जानकारी की भी मांग की।

उनके खिलाफ उत्पीड़न, इस याचिका पर कि वे उनके लिखित बयान को प्रस्तुत करने के लिए प्रासंगिक थे, जिसे प्रत्यर्थी सं. 2 - विश्वविद्यालय और उन्हें जवाब देने के लिए बीस दिन का समय दिया गया।

15. 15 अक्टूबर, 2009 को निर्वाचन आयोग ने तय किए गए आरोपों की जांच करने के लिए बॉम्बे उच्च न्यायालय के एक पूर्व न्यायाधीश को नियुक्त किया।

अपीलार्थी के खिलाफ और उसे सूचित किया गया कि जाँच अधिकारी करेगा 15 तिथि 4 जून, 2009

16 दिनांक 5 जून, 2009 17 पत्र के माध्यम से 17 सितंबर, 2009 [2023] 7 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

9 नवंबर, 2009 को उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों की प्रारंभिक जांच करें। 9 नवंबर, 2009 को आयोजित जांच समिति की पहली बैठक में अपीलार्थी और उनके अधिवक्ता ने विधिवत भाग लिया। दूसरी बैठक 7 दिसंबर, 2009 को निर्धारित की गई थी, जिस तारीख को प्रतिवादी नं. 2 - विश्वविद्यालय ने मेधा कोतवाल लेल के मामले में इस न्यायालय द्वारा पारित 26 मार्च, 2004 के फैसले को संदर्भित किया और

अन्य वी। भारत संघ और अन्य 18 1 8 और सी. सी. ए. (सी. सी. ए.) नियमों के नियम 14 (2) के परंतुक में संशोधन 1 9 जो यह प्रावधान करता है कि जहां केंद्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1964 2 0 के नियम 3 सी के अर्थ के भीतर यौन उत्पीड़न की शिकायत है, शिकायत समिति को इस उद्देश्य के लिए जांच करने वाला प्राधिकरण माना जाएगा।

जांच अधिकारी ने बड़े दंड लगाने के लिए जांच को स्थगित रखने का फैसला किया, ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मेधा कोतवाल के मामले (उपरोक्त) में कोई और निर्देश जारी किए गए थे।

16. 15 दिसंबर, 2009 को प्रत्यर्थी के पंजीयक नं. 2 - विश्वविद्यालय ने अपीलार्थी को सूचित किया कि अनुशासनात्मक कार्यवाही

निर्वाचन आयोग द्वारा 12 दिसंबर, 2009 को आयोजित अपनी बैठक में की गई सिफारिशों पर उनके खिलाफ शुरू किया गया आदेश समाप्त कर दिया गया था और जांच अधिकारी की नियुक्ति का आदेश भी 26 अप्रैल, 2004 के आदेश के आलोक में वापस ले लिया गया था, जो इस अदालत द्वारा मेधा कोतवाल के मामले में पारित किया गया था, जिसमें कहा गया था कि कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम के लिए शिकायत समिति की रिपोर्ट में कहा गया था: सी. सी. एस. (सी. सी. ए.) नियमों के तहत एक जांच रिपोर्ट मानी जाती है जो सरकारी कर्मचारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू करने के लिए अनुशासनात्मक प्राधिकरण पर बाध्यकारी होगी। निर्वाचन आयोग द्वारा 14 जून, 2009 को अपीलार्थी के खिलाफ लगाए गए आरोपों की जांच के लिए एक जांच अधिकारी नियुक्त करने के निर्णय को अनजाने में बताते हुए, पंजीयक ने अपीलार्थी को सूचित किया कि अनुशासनिक प्राधिकरण मौजूदा नियमों के तहत उसके खिलाफ आगे की कार्रवाई का फैसला करेगा।

ग. वितरण प्राधिकरण का निर्णय

और अपीलीय प्राधिकरण

17. इसके बाद प्रत्यर्थी सं. 21 के कुलपति द्वारा एक ज्ञापन जारी किया गया। 2 - विश्वविद्यालय की ओर से 18 (2013) 1 एससीसी 297

19 तिथि 1 जुलाई, 2004

20 सी. सी. एस. (आचरण) नियम

21 दिनांक 17 फरवरी, 2010 ऑरेलियानो फर्नांडीस बनाम।

गोवा राज्य और अन्य [हिमा कोहली, जे.]

निर्वाचन आयोग ने अपीलार्थी को सूचित किया कि 28 जनवरी, 2010 को आयोजित अपनी बैठक में निर्वाचन आयोग ने समिति की रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया था और निर्णय लिया था कि वह अपने खिलाफ लगाए गए आरोपों की गंभीरता को देखते हुए सेवा में बने रहने के लिए अयोग्य है। बर्खास्तगी का एक बड़ा जुर्माना लगाने का प्रस्ताव जिससे उसे भविष्य के रोजगार से अयोग्य घोषित किया जा सके नियम 2 2 के तहत विचार किए जाने पर, अपीलार्थी को अपना प्रतिनिधित्व प्रस्तुत करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया गया था।

18. अपीलार्थी ने 13 मार्च, 2010 को अपना जवाब प्रस्तुत किया। उसके जवाब की जांच करने के बाद, अनुशासनात्मक प्राधिकारी ने अपीलार्थी को खारिज कर दिया

10 मई, 2010 के आदेश के अनुसार सेवा से। अपील 2 3 को प्राथमिकता दी गई उत्त बर्खास्तगी आदेश के खिलाफ अपीलार्थी द्वारा अपील प्राधिकरण के आदेश 24 द्वारा खारिज कर दिया गया था।

D. उच्च न्यायालय का निर्णय

19. उक्त आदेशों को बॉम्बे उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी। उच्च न्यायालय ने कहा कि समिति ने अपीलार्थी को शिकायतकर्ताओं और गवाहों से जिरह करने के लिए पर्याप्त अवसर दिए थे, लेकिन उसने जानबूझकर उसके समक्ष उपस्थित नहीं होने का फैसला किया था। ऐसी परिस्थितियों में, समिति को उनके खिलाफ एकतरफा कार्यवाही करने और अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता था। यह भी माना गया कि

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत चिकित्सा प्रमाणपत्रों को खारिज करने में समिति को उचित ठहराया गया क्योंकि वह जांच कार्यवाही से दूर रहने के लिए तुच्छ बहाने बनाता रहा। अपीलार्थी की याचिका कि समिति का अनुचित रूप से गठन किया गया था या इसकी संरचना संदिग्ध थी क्योंकि इसमें विभाग में उनसे कनिष्ठ व्यक्ति शामिल थे, को अयोग्य बताते हुए खारिज कर दिया गया था। इसके अलावा, यह तर्क कि जांच निष्पक्ष और उचित दिए बिना अनुचित जल्दबाजी में की गई थी

अपीलार्थी को अपना बचाव करने का अवसर भी अस्वीकार कर दिया गया था। नतीजतन, उच्च न्यायालय ने उक्त रिट याचिका में कोई गुणदोष नहीं देखा, जिसे यह मानते हुए खारिज कर दिया गया था कि मामले में प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों और सेवा नियमों का कोई उल्लंघन नहीं हुआ था।

ई. सलाहकार द्वारा प्रस्तावित तर्क

पार्टियाँ:

(क) अपीलार्थी के लिए सलाह

22 नियम 11 (IX) सी. सी. एस. सी. ए., 1965 23 अपील दिनांक 25 जून, 2010 24 दिनांक 19 अप्रैल, 2010

25 गोवा के राज्यपाल और गोवा विश्वविद्यालय के कुलाधिपति 7 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

20. अपीलार्थी की ओर से तर्क देते हुए, श्री विश्वजीत

भट्टाचार्य, विद्वान वरिष्ठ वकील ने कई मामलों में विवादित फैसले की आलोचना की है। उनके तर्कों का मुख्य जोर यह है कि अनुशासनिक प्राधिकरण द्वारा पारित और अपीलीय प्राधिकरण द्वारा बरकरार रखा गया बर्खास्तगी आदेश पूरी तरह से समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर आधारित है जो एक तथ्य-खोज कार्यवाही से ज्यादा कुछ नहीं थी।

17 मार्च, 2009 को शुरू हुई और 5 जून, 2009 को समाप्त हुई कि हालांकि जांच कथित रूप से 17 मार्च, 2009 को शुरू हुई थी, लेकिन पहली सुनवाई वास्तव में 27 अप्रैल, 2009 को हुई थी और अठारह बैठकों के दौरान अड़तालीस दस्तावेजों और अड़तालीस बयानों पर भरोसा करके, अपीलार्थी को अपना बचाव करने और अपना मामला पेश करने का पर्याप्त अवसर दिए बिना, पूरी कार्यवाही को अड़तीस-नौ दिनों की अवधि के भीतर जल्दबाजी में बंद कर दिया गया था। यह तर्क दिया गया था कि यद्यपि समिति ने समय बढ़ाने के लिए अपीलार्थी के अनुरोध को स्वीकार कर लिया था और उसे 12 जून, 2009 तक का समय दिया था, लेकिन अवधि को अचानक लगभग एक महीने के लिए कम कर दिया गया था और तारीख को 14 मई, 2009 तक बढ़ा दिया गया था, बिना किसी औचित्य के और अपीलार्थी की अस्वस्थता की परवाह किए बिना, जैसा कि बताया गया था। जब अपीलार्थी ने समिति को अपनी आगे की गवाही और आगे की कार्यवाही के लिए एक नई तारीख की मांग करते हुए लिखा, तभी उसे पता चला कि समिति ने अपनी कार्यवाही पूरी कर ली है और 5 जून, 2009 को ही अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। इस प्रकार यह तर्क दिया जाता है कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत प्रत्यर्थियों द्वारा घोर उल्लंघन किया गया है और अपीलार्थी को सेवा से बर्खास्तगी का आदेश पारित करने से पहले एक निष्पक्ष परीक्षण के उचित अवसर से वंचित कर दिया गया है, जिससे वह गंभीर पूर्वाग्रह का कारण बनता है।

21. भारत संघ में इस न्यायालय के निर्णय का हवाला देते हुए और एक अन्य *v. तुलसीराम पटेल* 2 8, विद्वान वरिष्ठ वकील ने तर्क दिया कि इनमें से कोई भी नहीं

भारत के संविधान के अनुच्छेद 311 (2) के दूसरे परंतुक के तीन खंड जो यह आदेश देते हैं कि संघ या राज्य द्वारा नियोजित किसी भी व्यक्ति को सेवा से बर्खास्त या हटाया नहीं जाएगा, सिवाय इसके कि

याचिकाकर्ता को बर्खास्त करने के लिए आगे बढ़ने से पहले उचित जांच नहीं करने के लिए उत्तरदाताओं द्वारा जांच का सहारा लिया जा सकता था। यह जोरदार तर्क दिया गया कि सी. सी. एस. (सी. सी. ए.) नियमों के तहत निर्धारित प्रक्रिया के विपरीत, प्रतिवादियों द्वारा कोई उचित जांच नहीं की गई थी और पहली समिति द्वारा तब तक कोई आरोप नहीं बनाए गए थे जब तक कि

जिस तारीख को उसने अपनी रिपोर्ट 29 प्रस्तुत की थी और आरोप के लेख कि

26 दिनांक 10 मई, 2010 का आदेश 27 5 मई, 2009 का पत्र 28 (1985) 3 एस. सी. सी. 398

29 5 जून, 2009 के पत्र के माध्यम से ऑरेलियानो फर्नांडीस बनाम।

गोवा राज्य और अन्य [हिमा कोहली, जे.]

उत्तरदाताओं द्वारा 8 सितंबर, 2009 के ज्ञापन के माध्यम से तैयार किए गए थे, जिन्हें बाद में हटा दिया गया और पहली समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के पक्ष में आदेशित जांच को छोड़ दिया गया, जो केवल एक तथ्य खोजने वाली रिपोर्ट थी जिस पर अंतिम जांच के रूप में भरोसा नहीं किया जा सकता था, विशेष रूप से जब इसके गंभीर परिणाम होते। सीखा हुआ वरिष्ठ

वकील ने दिल्ली उच्च न्यायालय के एक विद्वान एकल न्यायाधीश के फैसले का हवाला दिया

संदीप खुराना बनाम में न्यायालय। दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड और अन्य 30 और प्रोफेसर गिरिधर मद्रास बनाम मामले में कर्नाटक उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश। भारतीय विज्ञान संस्थान का प्रतिनिधित्व अध्यक्ष और अन्य 31 ने यह आग्रह करने के लिए किया कि समिति की रिपोर्ट को एक जांच अधिकारी की रिपोर्ट के साथ नहीं जोड़ा जा सकता है, जैसा कि सी. सी. एस. (सी. सी. ए.) नियमों के नियम 14 में निर्धारित प्रक्रिया में माना गया है। निर्धारित प्रक्रिया के इस गैर-पालन ने अपीलार्थी के साथ गंभीर अन्याय किया है, यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का गंभीर उल्लंघन है। अपीलार्थी द्वारा पहली समिति के कुछ सदस्यों के खिलाफ पक्षपात के आरोप भी लगाए गए थे।

22. विद्वान वकील ने आगे तर्क दिया कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 311 (2) के दूसरे प्रावधान से जुड़े तीन खंडों में से किसी पर भी अपीलार्थी के खिलाफ उचित जांच करने की अव्यावहारिकता और समिति की ओर से विफलता को सही ठहराने के लिए दबाव नहीं डाला गया है।

सी. सी. एस. (सी. सी. ए.) नियमों में निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना ही पूरी कार्यवाही को दूषित करता है। वास्तव में, यह अपीलार्थी का मामला है कि किसी भी स्तर पर उसे समिति द्वारा सूचित नहीं किया गया था कि उसके द्वारा की जा रही कार्यवाही अनुशासनात्मक कार्यवाही थी और इसलिए, उक्त समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट को प्रतिवादियों द्वारा सी. सी. एस. (सी. सी. ए.) नियमों के तहत जांच रिपोर्ट के रूप में नहीं माना जा सकता था।

(ख) उत्तरदाताओं के लिए परामर्श सं। 2 और 3

23. दूसरी ओर, सुश्री रुचिरा गुप्ता, उत्तरदाताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वकील नं। 2 और 3 ने अपीलार्थी की ओर से दिए गए तर्कों का दृढ़ता से खंडन किया। उसने प्रस्तुत किया कि अपीलार्थी प्रत्यर्थी द्वारा लिए गए निर्णय को चुनौती देने में विफल रहा है। 2 - में विचार की गई जांच के साथ वितरण विश्वविद्यालय

8 सितंबर, 2009 का ज्ञापन, उपयुक्त स्तर पर, उन्हें देर से ऐसा करने से रोक दिया गया है। इस निवेदन को प्रमाणित करने के लिए, उन्होंने 18 अप्रैल, 2009 के अपने पत्र में अपीलार्थी द्वारा की गई प्रारंभिक आपत्तियों का उल्लेख किया, जिसमें उन्होंने पांच प्रारंभिक आपत्तियां उठाई थीं।

30 आई. एल. आर. 2006 (11) डेल 1313
3508 [2023] 7 एस. सी. आर.

31 (2019) एससीसी ऑनलाइन कार

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

समिति के पुनर्गठन और इसकी संरचना के संबंध में, समिति के दो सदस्यों द्वारा कथित रूप से उनके खिलाफ पूर्वाग्रह और यह तथ्य कि उन्हें उनके द्वारा मांगे गए अभिलेखों तक पहुंच से वंचित कर दिया गया था। लेकिन बाद में शिकायत को जांच करने के लिए समिति की क्षमता या अधिकार क्षेत्र के बारे में उठाया जाना चाहिए और

उसके द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया पर अपीलार्थी द्वारा कभी सवाल नहीं उठाया गया था। 24. समिति और अपीलार्थी के बीच आदान-प्रदान किए गए पत्राचार का उल्लेख करते हुए, विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि अपीलार्थी को अपना जवाब प्रस्तुत करने के लिए कम से कम तीन अवसर दिए गए थे और समिति द्वारा अठारह सुनवाई आयोजित की गई थी, लेकिन उन्होंने कई तारीखों पर कार्यवाही में भाग नहीं लिया। अपीलार्थी के पेश होने में विफल रहने और अस्वस्थता के तुच्छ बहाने बनाने और बार-बार अनुरोध करने के बाद ही

स्थगन, क्या समिति ने उनके खिलाफ एकतरफा कार्रवाई की और

5 जून, 2009 को पंजीयक को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस प्रकार यह तर्क दिया गया कि स्थिति किसी भी तरह से नहीं बदली होगी।

यदि अपीलार्थी को एक और अवसर दिया गया था, जैसा कि उसने 4 जून, 2009 के पत्र के माध्यम से अनुरोध किया था। इस संदर्भ में, न्यायालय का ध्यान सी. सी. एस. (सी. सी. ए.) नियमों के नियम 14 (2) के प्रावधान की ओर आकर्षित किया गया, जो शिकायत समिति को इस मामले की जांच करने का आदेश देता है।

यौन उत्पीड़न की शिकायत, "जहां तक व्यावहारिक हो", नियमों में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार। अविनाश मिश्रा बनाम में दिल्ली उच्च न्यायालय की खंड पीठ का निर्णय। भारत संघ को उत्तरदाताओं के रुख को सही ठहराने के लिए उद्धृत किया गया है कि "जहां तक व्यवहार्य है" अभिव्यक्ति स्वयं इंगित करती है कि समिति को पूरी प्रक्रिया का सख्ती से पालन नहीं करने का विवेकाधिकार निहित है जब तक कि आरोपित अधिकारी को स्पष्टीकरण देने का पर्याप्त अवसर दिया गया है।

शिकायत और प्रासंगिक सामग्री के संबंध में उनके रुख का खुलासा किया गया है।

25. उत्तरदाताओं के लिए विद्वान वकील नं. 2 और 3 ने आगे कहा कि समिति ने अपीलार्थी को पर्याप्त अवसर दिए थे

गवाहों से जिरह करना, अपने गवाहों को पेश करना और अपनी गवाही पूरी करना लेकिन वह किसी न किसी बहाने से कार्यवाही में देरी करते रहे। रिपोर्ट का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि यह दर्शाता है कि समिति ने अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत किए गए विस्तृत जवाब पर ध्यान दिया था

25 अप्रैल, 2009 को इस पर काफी विस्तार से विचार किया गया था। हीरा नाथ मिश्रा और अन्य बनाम में इस न्यायालय के फैसलों पर भी भरोसा रखा गया है। प्राचार्य, राजेंद्र मेडिकल कॉलेज, 2014 एस. सी. सी. ऑनलाइन डेल 1856 ऑरेलियानो फर्नांडीस बनाम।

गोवा राज्य और अन्य [हिमा कोहली, जे.]

रांची और अन्य 3 और पी. डी. अग्रवाल बनाम। भारतीय स्टेट बैंक और अन्य 3 4 का तर्क है कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत एक लचीले सिद्धांत नहीं हैं और प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों की जांच यह देखने के लिए की जानी चाहिए कि क्या प्राकृतिक न्याय की आवश्यकताएं पूरी होती हैं। वर्तमान मामले में, मामले की संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए जहां प्रतिवादी के सत्रह से कम छात्र नहीं। 2 - विश्वविद्यालय ने अपीलार्थी के खिलाफ यौन उत्पीड़न की शिकायतें प्रस्तुत की थीं, समिति ने संतुलन बनाकर अपने विवेक का प्रयोग किया और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन किए बिना कार्यवाही का संचालन किया, जो रिपोर्ट के अवलोकन से ही स्पष्ट होता है।

26. विद्वान वकील ने दूसरे पक्ष द्वारा की गई इस दलील का भी खंडन किया कि जांच करने से पहले आरोप के अनुच्छेदों को तैयार करने में समिति की विफलता ने अपीलार्थी के लिए गंभीर पूर्वाग्रह पैदा किया था। उसने प्रस्तुत किया कि शिकायतों का योग और सार अपीलार्थी को शुरू से ही अच्छी तरह से पता था और सभी शिकायतकर्ताओं और अन्य गवाहों के प्रासंगिक बयान उन्हें विधिवत प्रस्तुत किए गए थे। उन्हें उक्त शिकायतों का जवाब देने, गवाहों से जिरह करने और बचाव में अपने गवाहों को पेश करने का पर्याप्त अवसर दिया गया था। प्रत्यर्थी सं. के निर्णय की व्याख्या करते हुए। 2 - विश्वविद्यालय 8 सितंबर, 2009 के ज्ञापन के आधार पर अपीलार्थी के खिलाफ बाद में गठित जांच कार्यवाही को समाप्त करने के लिए, विद्वान वकील ने 26 अप्रैल, 2004 के आदेश की ओर इशारा करते हुए पारित किया

इस न्यायालय द्वारा मेधा कोतवाल के मामले (उपर्युक्त) में, जिसने स्पष्ट किया था कि शिकायत समिति जैसा कि विशाखा और अन्य में विचार किया गया है V. राजस्थान राज्य और अन्य 3, सी. सी. एस. (सी. सी. ए.) नियमों के प्रयोजनों के लिए जांच प्राधिकरण होंगे और उक्त समिति की रिपोर्ट को एक जांच रिपोर्ट माना जाएगा जिस पर अनुशासनात्मक प्राधिकरण

नियमों के अनुसार कार्य करेगा। यह प्रस्तुत किया गया था कि निर्वाचन आयोग ने अपीलार्थी के खिलाफ बनाए गए आरोपों की जांच के लिए एक जांच प्राधिकरण नियुक्त करके एक वास्तविक त्रुटि की थी और 15 अक्टूबर, 2009 के आदेश को वापस लेने के उक्त निर्णय को 15 दिसंबर, 2009 को अपीलार्थी को विधिवत सूचित किया गया था। इसके बाद ही, निर्वाचन आयोग ने अपीलार्थी को एक नया ज्ञापन 3 6 36 जारी किया जिसमें उससे समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट को स्वीकार करने के निर्णय पर अपना प्रतिनिधित्व प्रस्तुत करने और उस पर सेवा से बर्खास्तगी का एक बड़ा जुर्माना लगाने का आह्वान किया गया था। 33 (1973) 1 एस. सी. सी. 805

34 (2006) 8 एस. सी. सी. 776

35 (1997) 6 एस. सी. सी. 241
सी. आर.

36 दिनांक 17 फरवरी, 2010 [2023] 7 एस.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

27. इस प्रकार यह प्रस्तुत किया गया कि अपीलार्थी के प्रति कोई पूर्वाग्रह नहीं था और समिति ने मामले के दिए गए तथ्यों और परिस्थितियों में प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का "जहां तक व्यावहारिक था" पालन किया था। अपीलार्थी को न केवल समिति द्वारा, बल्कि अनुशासनिक प्राधिकरण और अपीलीय प्राधिकरण द्वारा भी पर्याप्त अवसर प्रदान किया गया था। उसके खिलाफ कोई भी कार्रवाई करने से पहले प्राधिकरण। इसलिए, यह "कोई अवसर नहीं" या "कोई सुनवाई नहीं" का मामला नहीं था, बल्कि अपीलार्थी पर सेवा से बर्खास्तगी का एक बड़ा जुर्माना लगाने से पहले "पर्याप्त अवसर" और "निष्पक्ष सुनवाई" का मामला था, जैसा कि सी. सी. ए. नियमों की धारा 11 (9) में निर्दिष्ट किया गया है।

एफ. द ट्रायड: संविधान के अनुच्छेद 309, 310 और 311

भारत का संविधान

28. संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं संविधान के भाग XIV के तहत शासित होती हैं। संविधान का अनुच्छेद 309 जो संघ या राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की भर्ती और सेवा की शर्तों का प्रावधान करता है, अनुच्छेद 310 जो संघ या राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों के पद के कार्यकाल को संदर्भित करता है और अनुच्छेद 311 जो नागरिक क्षमताओं में कार्यरत व्यक्तियों की बर्खास्तगी, निष्कासन या रैंक में कमी से संबंधित है। संघ या राज्य के तहत आपस में जुड़े हुए हैं और "एक एकीकृत संपूर्ण बनाते हैं, जिसमें एक जैविक और विषयगत होता है

एकता उनके माध्यम से चल रही है।

(क) अनुच्छेद 309: सेवा की शर्तें

29. अनुच्छेद 309 अपने आप में सरकारी कर्मचारियों की भर्ती या सेवा की शर्तों का प्रावधान नहीं करता है, लेकिन यह शक्ति उचित विधायिका को कानून बनाने के लिए और किसी राज्य के राष्ट्रपति और सरकार को इन मामलों से संबंधित नियम बनाने के लिए प्रदान करता है। अनुच्छेद 309 में "सेवा की शर्तें" की अभिव्यक्ति उन सभी शर्तों को व्यापक रूप से लेती है जो किसी व्यक्ति द्वारा किसी पद के धारण को विनियमित करती हैं जो उसके सेवा में प्रवेश करने के समय से लेकर उसकी सेवानिवृत्ति तक और यहां तक कि सेवानिवृत्ति के बाद तक, पेंशन जैसे मामलों के संबंध में, अनुशासनात्मक रूप से लंबित हैं।

कार्यवाही आदि। इस अभिव्यक्ति में ऐसे व्यक्ति को सेवा 38 से बर्खास्त करने का अधिकार भी शामिल है। एक कानून को उपयुक्त विधानमंडल द्वारा अधिनियमित किया जा सकता है या प्रक्रिया और प्राधिकरण को निर्धारित करने के लिए अनुच्छेद 309 के तहत उपयुक्त कार्यपालिका द्वारा नियम बनाए जा सकते हैं।

सरकारी कर्मचारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू करें। यह आगे है

37 भारत संघ और एक अन्य v. तुलसी राम पटेल, (1985) 3 एससीसी 398 38 मध्य प्रदेश राज्य और अन्य बनाम। शार्दुल सिंह, (1970) 1 एस. सी. सी. 108 39 बी. के. सरदार लाल बनाम। भारत संघ और अन्य, (1971) 1 एस. सी. सी. 411 ऑरलियानो फर्नांडीस बनाम।

गोवा राज्य और अन्य [हिमा कोहली, जे.]

यह अभिनिर्धारित किया गया है कि कोई भी अधिनियम या नियम जो अनुच्छेद 311 के तहत एक सरकारी कर्मचारी को गारंटीकृत अधिकारों का उल्लंघन करता है, अमान्य होगा। इसी तरह, इस तरह के एक अधिनियम या नियम को अमान्य माना जाएगा यदि यह किसी का उल्लंघन करता है

संविधान के भाग III के तहत गारंटीकृत मौलिक अधिकार।

(ख) अनुच्छेद 310: डॉक्ट्रिन ऑफ प्लीज

30. अनुच्छेद 310 "आनंद के सिद्धांत" का प्रतीक है और सरकारी कर्मचारियों के संदर्भ में, उनकी सेवा के कार्यकाल से संबंधित है। अनुच्छेद 310 (1) सरकारी कर्मचारियों के कार्यकाल को राष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल की इच्छा के अधीन बनाता है, सिवाय इसके कि स्पष्ट रूप से प्रावधान किया गया हो।

संविधान के अनुसार। यह अनुच्छेद इंग्लैंड में क्राउन के अधिकारों के अनुरूप है जहां क्राउन के सभी सार्वजनिक अधिकारियों और सेवकों को क्राउन की खुशी पर नियुक्त किया जाता है और उनकी सेवाओं को बिना कोई कारण बताए अपनी इच्छानुसार समाप्त किया जा सकता है। यही कारण है कि सरकारी कर्मचारी का कार्यकाल राष्ट्रपति या राज्य के राज्यपाल की इच्छा के अधीन है, सिवाय इसके कि संविधान के तहत स्पष्ट रूप से प्रावधान किया गया है। ऐसी सेवाओं के सभी सदस्य जो सरकारी खजाने से अपना वजीफा प्राप्त करते हैं, चाहे वे पदानुक्रम के शीर्ष पर हों या सबसे निचले स्तर पर, अंततः जनता के प्रति जवाबदेह होते हैं और उनसे अपेक्षा की जाती है कि वे जनता की उच्च भलाई के लिए अपने कर्तव्यों का जिम्मेदारी, कुशलता, प्रभावी और सबसे बड़कर निर्वहन करें। इसलिए, यह देखा जा सकता है कि हालांकि सरकारी कर्मचारियों की उत्पत्ति संविदात्मक हो सकती है, एक बार नियुक्त होने के बाद

पद या कार्यालय के लिए, वे एक दर्जा प्राप्त करते हैं और उनके अधिकार और दायित्व अब दोनों पक्षों की सहमति से निर्धारित नहीं होते हैं, बल्कि कानून या सांविधिक नियम 4 2 द्वारा शासित होते हैं।

(ग) अनुच्छेद 311: की एक व्याख्या

प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत

यह सुनिश्चित करना सरकार का कर्तव्य है कि लोक सेवक के खिलाफ इस तरह के किसी भी निर्णय से पहले एक जांच की जाए जो लोक सेवक को सुनवाई का अवसर देने पर विचार करती है, जो इस तरह के निर्णय के खिलाफ प्रतिनिधित्व करने का भी हकदार है। अनुच्छेद 311 इस प्रकार है - इसके अंतर्गत:

40 मोती राम डेका बनाम। महाप्रबंधक, उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे, (1964) 5 एससीआर 683

41 भारत संघ और एक अन्य v. तुलसी राम पटेल (1985) 3 एस. सी. सी. 398 42 रोशन लाल टंडन बनाम। भारत संघ, (1968) 1 एससीआर 185 43 निशा प्रिया भाटिया बनाम। भारत संघ और एक अन्य, (2020) 13 एस. सी. सी. 56 [2023] 7 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

" 311. व्यक्तियों को बर्खास्त करना, पद से हटाना या पद में कमी करना।

संघ या राज्य के तहत नागरिक क्षमताओं में कार्यरत। — (1) कोई भी व्यक्ति जो संघ की सिविल सेवा या अखिल भारतीय सेवा या किसी राज्य की सिविल सेवा का सदस्य है या संघ या राज्य के तहत सिविल पद धारण करता है, उसे संघ द्वारा बर्खास्त या हटाया नहीं जाएगा।

जिसके द्वारा उन्हें नियुक्त किया गया था, उसके अधीनस्थ प्राधिकारी।

(2) उपरोक्त किसी भी व्यक्ति को बर्खास्त नहीं किया जाएगा या

पद से हटा दिया गया या कम कर दिया गया, सिवाय उस जांच के जिसमें वह

उसके खिलाफ आरोपों के बारे में सूचित किया गया है और एक

उन आरोपों के संबंध में सुनवाई का उचित अवसर:

बशर्ते कि जहां ऐसी जांच के बाद उस पर ऐसा कोई जुर्माना लगाने का प्रस्ताव किया गया है, वहां ऐसा जुर्माना ऐसी जांच के दौरान दिए गए साक्ष्य के आधार पर लगाया जा सकता है और ऐसे व्यक्ति को ऐसा कोई अवसर देना आवश्यक नहीं होगा।

प्रस्तावित दंड पर प्रतिनिधित्व करना:

(क) जहाँ किसी व्यक्ति को बर्खास्त या हटा दिया जाता है या कम कर दिया जाता है।
आचरण के आधार पर पद जिसके कारण उसे दोषी ठहराया गया है

आपराधिक आरोप पर; या

(ख) जहाँ किसी व्यक्ति को बर्खास्त करने या हटाने या उसे पद से कम करने के लिए सशक्त प्राधिकारी का समाधान होता है कि कुछ लोगों के लिए

कारण, उस प्राधिकरण द्वारा लिखित रूप में दर्ज किया जाना, यह नहीं है

ऐसी जांच करने के लिए उचित रूप से व्यवहार्य; या

(ग) जहां, यथास्थिति, राष्ट्रपति या राज्यपाल का समाधान हो जाता है कि राज्य की सुरक्षा के हित में ऐसी जांच करना समीचीन नहीं है।

(3) यदि, उपरोक्त किसी व्यक्ति के संबंध में, कोई प्रश्न उत्पन्न होता है

क्या ऐसी जांच करना उचित रूप से व्यवहार्य है जो है -

पद अंतिम होगा।

32. सरकार को कार्यकाल की सुरक्षा की भावना प्रदान करना

एन. टी. एस., संविधान निर्माताओं ने सजा या बर्खास्तगी या हटाने या कम करने के सुरक्षा उपायों को शामिल किया है। जैसा कि अनुच्छेद 311 के खंड (1) और (2) में प्रावधान किया गया है। साथ ही

उसी लोक हित और लोक कल्याण के प्रति सचेत रहना ऑरिलियानो फर्नांडीस V.

गोवा राज्य और अन्य [हिमा कोहली, जे.]

बेईमानी या अक्षम को सेवा में जारी रखा जाए, अनुच्छेद 311 के खंड (2) के दूसरे परंतुक के तहत एक उपाय प्रदान किया जाता है, जिसके तहत अनुशासनात्मक जांच किए बिना उनकी सेवाओं को समाप्त किया जा सकता है।

33. इस प्रकार, अनुच्छेद 309, 310 और 311 के माध्यम से बुना गया सुनहरा धागा जनहित है, जो व्यापक सार्वजनिक भलाई की दिशा में निर्देशित है। एक साथ,

वे एक तिकड़ी बनाते हैं और सार्वजनिक नीति के व्यापक सिद्धांत का प्रतीक हैं।

जी. अनुच्छेद 14: के सिद्धांतों का आधार

प्राकृतिक न्याय

34. प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत जो अनुच्छेद 311 में परिलक्षित होते हैं, एक खाली मंत्र नहीं हैं। वे अनुच्छेद 14 का आधार हैं और इन सिद्धांतों का कोई भी उल्लंघन संविधान के अनुच्छेद 14 के उल्लंघन के समान है। प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों को अस्वीकार करना

35. अनुच्छेद 14, जिसे अक्सर प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के 'संवैधानिक संरक्षक' के रूप में वर्णित किया जाता है, स्पष्ट रूप से राज्य को, जैसा कि अनुच्छेद 12 में परिभाषित किया गया है, किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता या कानूनों के समान संरक्षण से वंचित करने से मना करता है। अनुच्छेद 14 समानता की स्पष्ट गारंटी प्रदान करता है।

कानून के समक्ष सभी व्यक्तियों को और किसी भी कानून द्वारा भेदभाव के खिलाफ उन्हें सुरक्षा प्रदान करता है। अनुच्छेद 13 (3) (ए) किसी भी अध्यादेश, आदेश, उप-कानून, नियम, विनियमन, अधिसूचना, प्रथा या भारत के क्षेत्र में कानून के बल वाले उपयोगों को शामिल करने के लिए कानून को परिभाषित करता है। इस प्रकार, के सिद्धांत

अनुच्छेद 14 के तहत गारंटीकृत प्राकृतिक न्याय, निर्णय लेने वाले न्यायनिर्णायक प्राधिकरण को कोई भी मनमाना कार्रवाई करने से रोकता है, चाहे वह मूल या प्रक्रियात्मक प्रकृति का हो। प्राकृतिक न्याय के ये सिद्धांत, जो एक प्राकृतिक कानून हैं, समय के साथ विकसित हुए हैं और व्यापक न्यायिक व्याख्या की प्रक्रिया के माध्यम से लगातार परिष्कृत किए गए हैं।

एच. द दिवन एंकर: नेमो जुडेक्स इन कौसा

एस. यू. ए. और ऑडी वैकल्पिक भागीदारी

36. जुड़वां लंगर जिन पर प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत हैं

न्यायिक प्रक्रिया में बाकी, चाहे अर्ध-न्यायिक या प्रशासनिक प्रकृति का हो, कोई भी व्यक्ति अपने स्वयं के मामले में न्यायाधीश नहीं होगा क्योंकि न्याय न केवल किया जाना चाहिए, बल्कि स्पष्ट रूप से किया जाता देखा जाना चाहिए और ऑडी अल्टेरम पार्टेम, यानी [2023] 7 एस. सी. आर. से प्रभावित व्यक्ति।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

न्यायिक, अर्ध-न्यायिक या प्रशासनिक कार्यवाई को कोई भी निर्णय लेने से पहले सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिए।

37. अदालतों ने प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों को संविधान में कितनी गहराई से शामिल किया है, यह मेनका गांधी बनाम के मामले में सात न्यायाधीशों की पीठ के फैसले से समझा जा सकता है। भारत संघ और एक अन्य "। इस मामले में, जहां अपीलार्थी के पासपोर्ट को जब्त करने के आदेश को चुनौती दी गई थी, जो ऐसी कार्यवाई के कारणों पर चुप था और प्रतिवादी-राज्य ने इसके लिए कारण प्रस्तुत करने से इनकार कर दिया था, यह अभिनिर्धारित किया गया था कि किसी व्यक्ति के जीवन और स्वतंत्रता को कानून द्वारा स्थापित किसी भी प्रक्रिया द्वारा प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता है, लेकिन केवल ऐसी प्रक्रिया द्वारा जो न्यायपूर्ण, निष्पक्ष और उचित हो। ऑडी अल्टरम पार्टेम नियम का हवाला देते हुए और इसे "कार्यवाई में निष्पक्ष खेल" के साथ तुलना करते हुए, न्यायमूर्ति पी. एन. भगवती (जैसा कि वे तब थे) ने बहुमत के लिए निर्णय लिखा था और कहा था कि:

" 14. ऑडी अल्टरम पार्टेम नियम एक कठोर सांचे में नहीं डाला गया है और न्यायिक निर्णय यह स्थापित करते हैं कि इसमें स्थितिजन्य संशोधन हो सकते हैं। हालाँकि, इसका मूल यह होना चाहिए कि प्रभावित व्यक्ति के पास होने का उचित अवसर होना चाहिए। सुनना और सुनना एक वास्तविक सुनवाई होनी चाहिए न कि एक खाली जनसंपर्क अभ्यास। यही कारण है कि टकर, एल. जे. ने रसेल बनाम में जोर दिया। ड्यूक ऑफ नॉरफॉक 45 ने कहा कि "प्राकृतिक न्याय का जो भी मानक अपनाया जाता है, एक आवश्यक बात यह है कि संबंधित व्यक्ति को अपना मामला पेश करने का उचित अवसर मिलना चाहिए"। क्या?

अवसर को उचित माना जा सकता है जो आवश्यक रूप से स्थिति की व्यावहारिक आवश्यकताओं पर निर्भर करेगा। यह एक परिष्कृत पूर्ण-स्तरीय सुनवाई हो सकती है या यह एक सुनवाई हो सकती है जो बहुत संक्षिप्त और न्यूनतम है: यह निर्णय से पहले की सुनवाई हो सकती है या यह निर्णय के बाद की उपचारात्मक सुनवाई भी हो सकती है। ऑडी अल्टरम पार्टेम नियम संशोधनों की अनुमति देने के लिए पर्याप्त रूप से लचीला है।

और असंख्य प्रकार की स्थितियों की आवश्यकताओं के अनुरूप परिवर्तन जो उत्पन्न हो सकते हैं।

38. शीर्षक वाले मामले में, रुस्तम कावासजी कूपर बनाम में इस न्यायालय की संविधान पीठ के फैसले का हवाला देते हुए। भारत संघ ",

46 (1970) 1 एस. सी. सी. 248 ऑरिलियानो फर्नांडीस बनाम। गोवा राज्य और अन्य [हिमा कोहली, जे.]

" तर्कसंगतता का सिद्धांत, जो कानूनी रूप से और साथ ही दार्शनिक रूप से, समानता या गैर मनमानेपन का एक आवश्यक तत्व है, अनुच्छेद 14 में एक सर्वव्यापी सर्वव्यापीता की तरह व्याप्त है। और अनुच्छेद 21 द्वारा अनुध्यात प्रक्रिया को अनुच्छेद के अनुरूप होने के लिए तर्कसंगतता की कसौटी का जवाब देना चाहिए।

14 "

न्यायिक प्रक्रिया द्वारा उनके अर्थ और सामग्री को कम करने के बजाय संविधान में गारंटीकृत मौलिक अधिकारों की पहुंच और दायरे का विस्तार करने के न्यायालय के प्रयास पर जोर दिया गया था।

निर्माण। ए. के. गोपालन बनाम के मामले में न्यायमूर्ति फजल अली द्वारा दिए गए अल्पमत निर्णय पर भरोसा करते हुए। मद्रास राज्य ", इस न्यायालय ने मेनका गांधी के मामले (उपरोक्त) में निर्णय दिया कि अनुच्छेद 21 के तहत निर्धारित की जाने वाली प्रक्रिया में चार आवश्यक शामिल होने चाहिए, अर्थात् नोटिस, सुनवाई का अवसर, निष्पक्ष न्यायाधिकरण और प्रक्रिया का सामान्य पाठ्यक्रम। यह देखा गया कि सिद्धांत रूप में भी, अनुच्छेद 21 पर अनुच्छेद 14 के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए, अनुच्छेद 21 द्वारा विचार की गई प्रक्रिया में तर्कसंगतता की अवधारणा को पेश किया जाना चाहिए।

39. दिल्ली परिवहन निगम बनाम। डी टी सी मजदूर

एक घरेलू जांच में अपने मामले को सामने रखा और प्राकृतिक न्याय और निष्पक्ष खेल के सिद्धांतों का पालन करने के लिए एक नियोक्ता की आवश्यकता, निम्नलिखित शब्द:

जो हमारे संविधान में व्याप्त है, यह माँग करता है कि इसका काफी हद तक और प्रक्रियात्मक रूप से पालन किया जाना चाहिए। कानून का मानना है कि शक्ति का प्रयोग इस तरह से किया जाना चाहिए जो न्यायपूर्ण, निष्पक्ष और उचित हो और अनुचित न हो।

47 1950 एस. सी. सी. 228 48 (1991) सप्लीमेंट (1) एस. सी. सी. 600 [2023] 7 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

पक्षपातपूर्ण या मनमाना तरीके से भेदभाव की गुंजाइश छोड़ते हुए।

[जोर दिया गया]

XXX XXX XXX

316. इस प्रकार यह माना जा सकता है कि अनुच्छेद 14 को अनुच्छेद 16 (1) के साथ पढ़ा जाए।

प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुरूप समानता या समान व्यवहार का अधिकार प्रदान करता है। अनुच्छेद 12 के तहत नियोक्ता द्वारा बनाई गई किसी भी कानून या की गई कार्रवाई, कॉर्पोरेट वैधानिकता या साधन को निष्पक्ष, न्यायसंगत और यथोचित रूप से कार्य करना चाहिए। निष्पक्ष व्यवहार का अधिकार प्राकृतिक न्याय का एक अनिवार्य अंग है। बेलगाम और अनधिकृत विवेकाधीन शक्ति का प्रयोग नागरिक के अधिकार को बाधित करता है; विवेकाधिकार निहित करना कोई गलत नहीं है बशर्ते इसका उपयोग उद्देश्यपूर्ण रूप से विवेकपूर्ण और पूर्वाग्रह के बिना किया जाए। विवेकाधिकार जितना व्यापक होगा, दुरुपयोग की संभावना उतनी ही अधिक होगी। मनुष्य के अन्य आविष्कारों की तुलना में पूर्ण विवेक स्वतंत्रता का विनाशकारी है। पूर्ण विवेकाधिकार स्वतंत्रता के अंत की शुरुआत को चिह्नित करता है। स्थायी कर्मचारी को बर्खास्त करने की पूर्ण शक्ति प्रदान करना है -

न्याय या निष्पक्ष व्यवहार के प्रति विरोधाभास। इसका अभ्यास

व्यापक विवेकाधीन शक्ति मनमाने, अनुचित या अनुचित कार्यों को जन्म देगी और तर्क और न्याय के अनुरूप नहीं होगी। एक कानून, विनियमों या नियमों के प्रावधान जो एक नियोक्ता या को सशक्त बनाते हैं

पद से हटाने या कम करने के लिए प्रबंधन

न्यायसंगत, निष्पक्ष और उचित प्रक्रिया के अनुसार समाप्त किया गया।
करने वाला कोई भी कानून या नियम अमान्य है। ”

अन्यथा इसका उल्लंघन

[जोर जोड़ा गया] ऑरिलियानो फर्नांडीस बनाम। गोवा राज्य और अन्य [हिमा कोहली, जे.]

40. प्रक्रियात्मक निष्पक्षता द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका

संविधान में प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों को शामिल करने की पृष्ठभूमि को अतिरंजित नहीं किया जा सकता है। इस पहलू को इस न्यायालय की एक खंड पीठ द्वारा उजागर किया गया है, जिसमें हम में से एक, [हिमा कोहली, जे],

सदस्य, मध्यमम ब्रॉडकास्टिंग लिमिटेड बनाम। भारत संघ और अन्य "। पीठ की ओर से बोलते हुए मुख्य न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़ ने कहा:

" 53. मेनका गांधी (ऊपर) में इस न्यायालय का निर्णय

प्रक्रियात्मक निष्पक्षता पर दो सैद्धांतिक बदलावों का नेतृत्व किया क्योंकि

प्राकृतिक न्याय का संवैधानिककरण। सबसे पहले, प्रक्रियात्मक

निष्पक्षता को अब केवल न्याय सुनिश्चित करने के साधन के रूप में नहीं देखा जाता था परिणाम लेकिन एक ऐसी आवश्यकता जो अपने आप में एक अंतर्निहित मूल्य रखती है।

इस बदलाव को ध्यान में रखते हुए, अदालतों को अब पूरी तरह से बाहर रखा गया है।

इस आधार पर प्रक्रियात्मक उल्लंघनों का आकलन करना कि क्या

प्रक्रिया ने मामले के परिणाम पर प्रतिकूल प्रभाव डाला होगा।

इसके बजाय, अदालतों को यह तय करना होगा कि क्या प्रक्रिया

जिसका पालन एक मेले के अधिकार का उल्लंघन किया गया था और उचित प्रक्रिया, परिणाम से स्वतंत्र। में।

इस विचार के साथ अनुपालन, अदालतों ने पढ़ा है

प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों को इसे होने से बचाने के लिए एक अधिनियम में

प्रक्रियात्मक आधार पर असंवैधानिक घोषित किया गया। दूसरा, प्राकृतिक

न्याय के सिद्धांत प्रक्रिया में तर्कसंगतता की सांस लेते हैं।

इस तर्क का जवाब देते हुए कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत

स्थिर नहीं हैं लेकिन ढाले जाने में सक्षम हैं

परिस्थितियों में, यह माना गया था कि प्राकृतिक न्याय का मूल

एक उचित प्रक्रिया की गारंटी देता है जो एक संवैधानिक प्रक्रिया है।

अनुच्छेद 14, 19 और 21 में निहित आवश्यकता। का पहलू

ऑडी अल्टरम पार्टमें में इसके घटक शामिल हैं -

ऐसी सामग्री जो अवलोकन के लिए उपलब्ध हो। जबकि स्थितिजन्य संशोधन अनुमत हैं, प्राकृतिक न्याय के नियम

स्थिति की आवश्यकताओं के अनुरूप संशोधित नहीं किया जा सकता है

इस हद तक कि सिद्धांत के मूल को निरस्त कर दिया जाता है क्योंकि

न्यायनिर्णायक प्राधिकारी द्वारा अनुसरण (या पालन नहीं किया गया), प्रभावी रूप से, निष्पक्ष और उचित सुनवाई के अधिकार के मूल का उल्लंघन करता है।

- [जोर दिया

गया]

49 (2023) एससीसी ऑनलाइन 366 [2023] 7 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

41. ए. के. काईपाक और अन्य बनाम। भारत संघ और अन्य 50

एनजी अनुमोदन के साथ निर्णय पुनः एच. के. (सभी शिशु) 5 1, यह न्यायालय टोपी:

" 20. प्राकृतिक न्याय के नियमों का उद्देश्य न्याय प्राप्त करना है या

न्याय की विफलता को रोकने के लिए इसे नकारात्मक रूप से रखना। ये हैं नियम

केवल उन क्षेत्रों में काम कर सकते हैं जो वैध रूप से बनाए गए किसी कानून के दायरे में नहीं आते हैं। में। अन्य शब्द वे देश के कानून को प्रतिस्थापित नहीं करते हैं लेकिन पूरक हैं

यह। प्राकृतिक न्याय की अवधारणा ने बहुत कुछ झेला है

हाल के वर्षों में परिवर्तन। अतीत में यह सोचा गया था कि इसमें शामिल हैं

बस दो नियम नामधारी: (1) कोई भी अपने मामले में न्यायाधीश नहीं होगा।

(2) कोई निर्णय नहीं

किसी पक्षकार के विरुद्ध उसे उचित आश्वासन दिए बिना दिया जाएगा।

श्रवण (ऑडी अल्टरम पार्टम)। इसके तुरंत बाद एक तीसरा नियम परिकल्पना की गई थी और वह यह है कि अर्ध-न्यायिक जांच होनी चाहिए

अच्छे विश्वास में, बिना पूर्वाग्रह के और मनमाने ढंग से या अनुचित रूप से नहीं।

लेकिन वर्षों के दौरान कई और सहायक नियम बने प्राकृतिक न्याय के नियमों में जोड़ा गया। कुछ समय पहले तक यह

न्यायालयों की राय है कि जब तक संबंधित प्राधिकारी नहीं था

जिस कानून के तहत यह न्यायिक रूप से कार्य करने के लिए आवश्यक था प्राकृतिक न्याय के नियमों को लागू करने के लिए कोई जगह नहीं थी।

उस सीमा की वैधता पर अब सवाल उठाया जाता है। अगर मकसद

प्राकृतिक न्याय के नियमों का गर्भपात को रोकने के लिए है

न्याय यह देखने में विफल रहता है कि उन नियमों को क्यों बनाया जाना चाहिए

प्रशासनिक पृष्ठताछ के लिए लागू नहीं। अक्सर ऐसा होता है

प्रशासनिक सीमांकन वाली रेखा खींचना आसान नहीं है

अर्ध-न्यायिक पूछताछ से पूछताछ। पूछताछ जो

प्रशासनिक पूछताछ के रूप में। एक अन्यायपूर्ण निर्णय प्रभाव हो सकता है।

एक अर्ध-न्यायिक जांच में एक निर्णय की तुलना में।

प्रशासनिक जाँच का अधिक दूरगामी

99

- [जोर दिया गया]

1. सेवा में निष्पक्ष कार्रवाई और महत्व

न्यायनिर्णय:

59) 2 एससीसी 262

57) 1 सभी ई. आर. 226 ऑरिलियानो फर्नांडीस बनाम। गोवा राज्य और अन्य [हिमा कोहली, जे.]

42. सेवा कानून के संदर्भ में, इसलिए यह अनिवार्य है कि -

किसी सरकारी कर्मचारी या कर्मचारी को आदेश पारित करने से पहले सुनवाई का उचित अवसर प्रदान करना। मंगीलाल वी. इस न्यायालय ने घोषणा की कि भले ही कोई कानून मौन है और अधिनियम या उसके तहत बनाए गए नियमों में कोई सकारात्मक शब्द नहीं हैं, लेकिन प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन किया जाना चाहिए। अदालत ने यह फैसला सुनाया है:

" 10 जहाँ कानून प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के पालन के बारे में चुप है, वहाँ इस तरह के वैधानिक मौन को प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुपालन को दर्शाने के लिए लिया जाता है जहाँ पक्षों के पर्याप्त अधिकार काफी प्रभावित होते हैं। प्राकृतिक न्याय का अनुप्रयोग अनुमानित हो जाता है, जब तक कि कानून के स्पष्ट शब्दों या आवश्यक इरादे से बाहर नहीं पाया जाता है। (देखें स्वदेशी कॉटन मिल्स बनाम। भारत संघ 53 5 3) इसका उद्देश्य न्याय प्राप्त करना या न्याय की विफलता को रोकना है। प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत

कानून को प्रतिस्थापित नहीं करते हैं, बल्कि इसे पूरक बनाते हैं। ये नियम केवल उन क्षेत्रों में काम करते हैं जो वैध रूप से बनाए गए किसी भी कानून के दायरे में नहीं आते हैं। वे एक साधन हैं

एक अंत तक और अपने आप में एक अंत नहीं।

43. तुलसीराम पटेल के मामले (ऊपर) में, यह देखते हुए कि प्राकृतिक न्याय के नियमों के उल्लंघन के परिणामस्वरूप मनमानी होगी जो भेदभाव के समान, संविधान पीठ ने निम्नलिखित टिप्पणियां कीं:

" 95. इस प्रकार प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत सामने आए हैं।

में निहित गारंटी के एक भाग के रूप में मान्यता प्राप्त

अनुच्छेद 14 नई और गतिशील व्याख्या के कारण

इस न्यायालय द्वारा समानता की अवधारणा को दिया गया है जो है

उस लेख का विषय-वस्तु। संक्षेप में, शब्दांश इस प्रकार चलता है: प्राकृतिक न्याय के नियम के उल्लंघन के परिणामस्वरूप मनमानेपन होता है जो भेदभाव के समान है; जहां भेदभाव राज्य की कार्रवाई का परिणाम है, यह अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है: इसलिए, राज्य की कार्रवाई द्वारा प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है। हालाँकि, अनुच्छेद 14 एकमात्र भंडार नहीं है।

प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत। यह इस बात की गारंटी देता है कि उनका उल्लंघन करने वाले किसी भी कानून या राज्य की कार्रवाई को रद्द कर दिया जाएगा। प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत, हालांकि, न केवल कानून और राज्य की कार्रवाई पर लागू होते हैं, बल्कि उन जगहों पर भी लागू होते हैं जहां कोई न्यायाधिकरण, प्राधिकरण या व्यक्तियों का निकाय, परिभाषा के भीतर नहीं आता है।

52 (2004) 2 एस. सी. सी. 447
सी. आर.

53 (1981) 1 एससीसी 664 [2023] 7 एस.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

अनुच्छेद 12 में राज्य को निर्णय लेने का कर्तव्य सौंपा गया है

बात है। ऐसे मामले में प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत

यह आवश्यक है कि उसे इस तरह के मामले को निष्पक्ष और निष्पक्ष रूप से तय करना चाहिए।

96. प्राकृतिक न्याय का नियम जिससे हम संबंधित हैं इन अपीलों और रिट याचिकाओं में, अर्थात्, ऑडी अल्टरम

पार्टेम नियम, अपने पूर्ण आयाम में इसका मतलब है कि एक व्यक्ति

जिनके खिलाफ उसके पूर्वग्रह का आदेश पारित किया जा सकता है

उनके खिलाफ आरोपों और आरोपों के बारे में सूचित किया जाना चाहिए

उसे अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाए।

अतः, मौखिक या दोनों तरह से साक्ष्य जानने का अधिकार है।

उसके खिलाफ, और उन दस्तावेजों का निरीक्षण करना जिन पर भरोसा किया जाता है उसके खिलाफ इस्तेमाल किए जाने के उद्देश्य से,

गवाह जो उसके खिलाफ सबूत देने वाले हैं

उसकी उपस्थिति में जाँच की गई और उसे पार करने का अधिकार है

उनकी जाँच करें, और अपने स्वयं के साक्ष्य का नेतृत्व करें, दोनों मौखिक और वृत्तचित्र, उनके बचाव में। निष्पक्ष सुनवाई की प्रक्रिया

तथापि, न्यायालय में न्यायिक प्रक्रिया के अनुरूप होने की आवश्यकता नहीं है। कारणों के न्यायिक निर्णय में कई शामिल हैं कानून, क्योंकि

प्रक्रिया और साक्ष्य के तकनीकी नियम जो अनावश्यक हैं

और एक निष्पक्ष सुनवाई के उद्देश्य के लिए आवश्यक नहीं

अर्ध-न्यायिक या न्यायिक में ऑडी अल्टरम पार्टेम नियम का अर्थ

प्रशासनिक जाँच। यदि हम अनुच्छेद 311 के खंड (2) को देखें

ऊपर जो कहा गया है उसके आलोक में, यह स्पष्ट होगा कि वह खंड

केवल ऑडी अल्टरम पार्टेम नियम का एक स्पष्ट कथन है

जिसे निहित रूप से अनुच्छेद में निहित गारंटी का हिस्सा बनाया गया है

14 द्वारा उस लेख पर रखी गई व्याख्या के परिणामस्वरूप

इस न्यायालय के हाल के निर्णय। अनुच्छेद 311 का खंड (2) आवश्यक करता है

कि इससे पहले कि एक सरकारी कर्मचारी को बर्खास्त किया जाए, हटा दिया जाए या पद में कमी, एक जांच आयोजित की जानी चाहिए जिसमें वह है

उसके खिलाफ आरोपों के बारे में सूचित किया गया और एक उचित दिया गया

उन आरोपों के संबंध में सुनवाई का अवसर।

99

- [जोर दिया गया]

उसी समय, कैप्शन में सावधानी का एक नोट जोड़ा गया था

और न्यायालय ने कहा कि प्राकृतिक न्याय के नियम न तो कोरी नियम हैं और न ही वे पत्थर में ढाले गए हैं। वे लचीले होते हैं और विभिन्न ऑरिलियानो फ़र्नांडेस V की आवश्यकताओं के आधार पर कानूनों द्वारा संशोधित और संशोधित किए जा सकते हैं।

गोवा राज्य और अन्य [हिमा कोहली, जे.]

स्थितियों, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों और कानून की रूपरेखा 54।

44. स्वदेशी कॉटन मिल्स बनाम। भारत संघ, 55 में

असहमत निर्णय देते हुए न्यायमूर्ति ओ. चिन्नाप्पा रेड्डी ने निम्नलिखित प्रासंगिक टिप्पणियां की थीं:

" 106. प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों ने गहरी जड़ें जमा ली हैं

डॉ. बीना द्वारा पोषित हमारे लोगों की न्यायिक अंतरात्मा

पानी 5, ए. के. क्राईपक ", मोहिंदर सिंह गिल 58, मेनका

गाँधी 5 9. उन्हें अब इतना बुनियादी माना जाता है कि

" आदेशित स्वतंत्रता की अवधारणा में निहित और इसलिए, निहित

प्रत्येक निर्णय लेने के कार्य में, इसे न्यायिक, अर्ध-न्यायिक या

प्रशासनिक। जहाँ प्राधिकरण एक कानून के तहत कार्य करता है और कानून के सिद्धांतों के पालन के लिए प्रदान करता है

प्राकृतिक न्याय एक विशेष तरीके से, प्राकृतिक न्याय होगा

इसे उस तरीके से देखा जाना चाहिए और किसी अन्य तरीके से नहीं। नहीं। कानून द्वारा प्रदान किए गए अधिकार से अधिक व्यापक अधिकार का दावा किया जा सकता है

न ही अधिकार को संकुचित किया जा सकता है। जहाँ कानून चुप है प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के पालन के बारे में,

इस तरह के वैधानिक मौन का अनुपालन करने के लिए लिया जाता है

प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत। प्राकृतिक प्रभाव

न्याय अनुमानित होने के कारण इसे व्यक्त शब्दों द्वारा बाहर रखा जा सकता है

कानून या आवश्यक इरादे से। जहाँ के बीच संघर्ष है

लोक हित और निजी हित, अनुमान होना चाहिए अनिवार्य रूप से कमजोर हो और इसलिए, आसानी से विस्थापित हो सकता है।

" 9

- [जोर दिया

गया]

45. इस प्रकार, आम तौर पर, अदालतें सांविधिक प्रावधानों की व्याख्या समन्वय में करती हैं।

प्राकृतिक न्याय के उपरोक्त सिद्धांतों के साथ इस आधार पर कि कोई भी वैधानिक प्राधिकरण संविधान में निहित मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं करेगा। जब उन अधिकारियों की बात आती है जिनसे न्यायिक और अर्ध-न्यायिक कार्यों का निर्वहन करने की अपेक्षा की जाती है, तो ऑडी अल्टरम पार्टेम का नियम समान बल के साथ लागू होता है। तर्कसंगतता प्रक्रियात्मक जीवन में जीवन का संचार करती है।

54 यह भी देखें - A.K.Kraipak और अन्य v. भारत संघ और अन्य, (1969) 2 एस. सी. सी. 262 और भारत संघ बनाम। कर्नल जे. एन. सिन्हा और अन्य, (1970) 2 एस. सी. सी. 458

56 ए. आई. आर 1967 एस. सी. 1269

57 (1969) 2 एससीसी 262

(1978) 1 एस. सी. सी. 405

59 (1978) 1 एससीसी 248 [2023] 7 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

मामला, चाहे वह नोटिस के तत्व हों, नोटिस की सामग्री, जांच का दायरा, उपलब्ध सामग्री या ऐसी सामग्री का खंडन करने का पर्याप्त अवसर हो। यह सब किसी भी स्थिति में न्याय की विफलता से बचने के लिए है।

स्टेज। यह निश्चित रूप से तरल है और किसी मामले के दिए गए तथ्यों में स्थिति की मांगों के अनुकूल होने के अधीन है।

जे. द स्टेच्यूटरी रेजीम

(क) गोवा विश्वविद्यालय की स्थिति

46. उपरोक्त पृष्ठभूमि में, अब हम प्रासंगिक नियमों की जांच करने के लिए आगे बढ़ सकते हैं जो इसमें अपीलार्थी की सेवा की शर्तों को नियंत्रित करते हैं। प्रत्यर्थी सं. में नियोजित शिक्षकों के संबंध में सांविधिक व्यवस्था। 2- विश्वविद्यालय गोवा विश्वविद्यालय संविधि एसएसबी-1 (XXVI) द्वारा शासित है। कानून के एससी-6 (i) में निम्नानुसार विचार किया गया है -

" अनुशासनात्मक और विभागीय कार्रवाई के लिए, शिक्षकों को गोवा सरकार के कर्मचारियों पर लागू होने वाले सी. सी. एस. (सी. सी. ए.) नियम, 1965, मौलिक नियम और पूरक नियमों के तहत नियंत्रित किया जाएगा। (

ख) सी. सी. एस. (सी. सी. ए.) नियम:

47. ऊपर उल्लिखित सी. सी. एस. (सी. सी. ए.) नियम, भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिनियमित किए गए हैं।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 148 के अनुच्छेद 309 और खंड 5 का प्रावधान। सी. सी. एस. (सी. सी. ए.) नियमों का भाग VI डंड लगाने की प्रक्रियाओं को निर्धारित करता है। नियम 3 (सी) को जी. एस. आर. 49 दिनांक 7 मार्च, 1998 और बाद में जी. एस. आर. 823 (ई) दिनांक 19 नवंबर, 2014 के माध्यम से सी. सी. ए. नियमों में शामिल किया गया है। उक्त प्रावधान इस प्रकार है:

" 3 सी. कामकाजी महिलाओं के यौन उत्पीड़न पर प्रतिबंध

(1) कोई भी सरकारी कर्मचारी यौन संबंध बनाने के किसी भी कार्य में लिप्त नहीं होगा।

(2) प्रत्येक सरकारी कर्मचारी जो किसी कार्यस्थल का प्रभारी है, किसी भी व्यक्ति के यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए उचित कदम उठाएगा। कार्यस्थल पर महिला।

स्पष्टीकरण-(1) इस नियम के प्रयोजन के लिए -

(क) "यौन उत्पीड़न" में निम्नलिखित में से कोई एक या अधिक कार्य या व्यवहार (चाहे प्रत्यक्ष रूप से या निहितार्थ से) शामिल हैं, अर्थात् -

(i) शारीरिक संपर्क और प्रगति; या रेलेनो फर्नांडिस V.

गोवा राज्य और अन्य [हिमा कोहली, जे.]

((ख) यौन संबंध बनाने की मांग या अनुरोध; या

(ग) "जितना दूर हो सके" का व्यावहारिक अनुप्रयोग व्यावहारिक नियम है।

48. सी. सी. एस. (सी. सी. ए.) नियमों के नियम 14 में प्रमुख दंड के लिए प्रक्रिया निर्धारित की गई है और इसे नीचे निकाला गया है:

" 14. बड़े जुर्माने लगाने की प्रक्रिया (1)

खंडों में निर्दिष्ट किसी भी दंड को लागू करने का कोई आदेश नहीं

जब भी अनुशासनात्मक प्राधिकारी की राय होती है कि उस अधिनियम के तहत आयोजित।

(2)

किसी भी आरोप की सच्चाई की जांच करने के लिए आधार हैं

नियुक्ति कर सकता है।
सेवक, यह स्वयं इस नियम के तहत या लोक सेवकों (पूछताछ) के प्रावधानों के तहत जांच या
अधिनियम, 1850, जैसा भी मामला हो, इसकी सच्चाई की जांच करने का एक प्राधिकरण है।

बशर्ते कि जहाँ यौन संबंध की शिकायत हो

नियम 3 सी के अर्थ के भीतर उत्पीड़न

केंद्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1964

अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा नियुक्त प्राधिकारी शिकायतों को जांच माना जाएगा।

इन नियमों और शिकायतों का उद्देश्य

उत्पीड़न, [2023] 7 एस. सी. आर. में यथासंभव जांच। यौन शिकायतों की जांच करना

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

इन में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार

नियम "।

[जोर दिया

गया]

49. जैसा कि उपरोक्त से देखा जा सकता है, जब कदाचार संबंधित होता है

कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की शिकायत के लिए, प्रतिवादी द्वारा गठित शिकायत समिति नं। 2 - विश्वविद्यालय इस तरह की शिकायत की जांच करने के लिए, पूछताछ करने वाले प्राधिकरण की जिम्मेदारी संभालता है और उससे अपेक्षा की जाती है कि वह नियमों में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, जहां तक संभव हो, जांच करे। इसका उपयोग

"जहाँ तक व्यवहार्य है" अभिव्यक्ति प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों से समझौता किए बिना कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न जैसे संवेदनशील मामले में जांच करने के लिए एक निष्पक्ष प्रक्रिया को अपनाने के लिए शिकायत समिति के लिए उपलब्ध जोड़ों में एक खेल को इंगित करती है जो व्यवहार्य और लोचदार है। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि प्रत्येक मामले में तथ्य स्थिति अलग-अलग होगी और इसलिए इस तरह की शिकायतों में जांच करने के लिए कोई निर्धारित मानक या पैमाना निर्धारित नहीं किया जा सकता है। हालांकि, उन गंभीर प्रभावों को ध्यान में रखते हुए जिनके साथ जांच के अंत में अपराधी कर्मचारी से मुलाकात की जा सकती है, किसी भी विसंगत नोट या तथ्य की गई प्रक्रियाओं से अनुचित विचलन की आवश्यकता है

हालाँकि, अंतिम परिणाम के बावजूद, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के मूल पर प्रहार करेगा।

के. "विशाखा" केस से लेकर पोस तक की यात्रा

एक्ट

(क) विशाखा दिशानिर्देश: फिल्लिंग इन

वैक्यूम:

48. सीसीएस (सीसीए) नियमों के नियम 14 (2) में संशोधन का अवसर

और उसमें एक परंतुक संलग्न करना न्यायिक प्रक्रिया का प्रत्यक्ष परिणाम था।

विशाखा (ऊपर) के मामले में इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप, जहां भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग किया गया था

तीन न्यायाधीशों की पीठ द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 14,15,19 (1) (जी) और 21 के तहत प्रदत्त "लैंगिक समानता और जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार" के लिए महिलाओं के मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए। आंदोलन कर रहे कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं और गैर सरकारी संगठनों द्वारा दायर रिट याचिकाओं के एक समूह का इलाज करना

राजस्थान के एक गाँव में एक सामाजिक कार्यकर्ता के साथ क्रूर सामूहिक बलात्कार को एक वर्ग कार्रवाई के रूप में, इस न्यायालय ने मौजूदा कानून में रिक्तता को भरने की दिशा में काम किया। के लिए प्रावधान करने के लिए अधिनियमित किसी भी कानून की अनुपस्थिति को ध्यान में रखते हुए लैंगिक समानता और ऑरिलियानो फर्नांडीस के बुनियादी मानव अधिकार का प्रभावी प्रवर्तन।

गोवा राज्य और अन्य [हिमा कोहली, जे.]

यौन शोषण के खिलाफ गारंटी, विशेष रूप से यौन उत्पीड़न के खिलाफ कार्यस्थलों पर, न्यायालय ने अनुच्छेद 1560, अनुच्छेद 426 1 और अनुच्छेद 51 (ए) 62 सहित भारत के संविधान के कई प्रावधानों और सी. ई. डी. ए. डब्ल्यू. 6 3 की सामान्य सिफारिशों सहित प्रासंगिक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों और मानदंडों की सहायता से बल प्राप्त किया।

25 जून, 1993 को एक प्रस्ताव पारित किया गया था, जिसमें यह संकल्प लिया गया था कि कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से निपटने के लिए एक प्रभावी शिकायत तंत्र स्थापित किया जाए, इस निर्देश के साथ दिशानिर्देशों और मानदंडों का एक सेट निर्धारित किया गया था कि उनका सभी कार्यस्थलों पर सख्ती से पालन किया जाएगा और जब तक रिक्तता को भरा नहीं जाता है और क्षेत्र पर कब्जा करने के लिए एक कानून लागू नहीं किया जाता है, तब तक वे बाध्यकारी और कानून में लागू करने योग्य होंगे। दिशानिर्देशों में शिकायतों का समयबद्ध उपचार सुनिश्चित करने के लिए एक शिकायत तंत्र के निर्माण का निर्देश दिया गया, एक शिकायत समिति का गठन किया गया और अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश की गई, जहां इस तरह का आचरण 'संबंधित सेवा नियमों द्वारा परिभाषित' रोजगार में कदाचार के बराबर है। विशाखा के मामले (उपरोक्त) में महत्वपूर्ण निर्णय 13 अगस्त, 1997 को दिया गया था और न्यायालय द्वारा घोषित दिशानिर्देश कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और संरक्षण) तक जारी रहे।

निवारण) अधिनियम, 2013 को 22 अप्रैल, 2013 को लागू किया गया था।

(ख) मेधा कोतवाल का मामला: आगे बढ़ें
निरंतर नियम के माध्यम से:

49. विशाखा के मामले (ऊपर) के बाद, मेधा कोतवाल लेल और अन्य बनाम का मामला आया। भारत संघ और अन्य 65 (ऊपर) जहां एक

कई याचिकाकर्ताओं द्वारा शिकायत की गई थी कि शिकायत समितियों को निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार गठित करने का निर्देश दिया गया था

इस न्यायालय द्वारा यौन उत्पीड़न के मामलों से निपटने के लिए स्थापित नहीं किया गया था। उक्त याचिका को जनहित याचिका मानते हुए, भारत संघ और राज्य सरकारों सहित कई पक्षों को नोटिस जारी किए गए और निम्नलिखित निर्देश जारी किए गए:

60 अनुच्छेद 15: राज्य किसी भी नागरिक के साथ धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। 61 अनुच्छेद 42: राज्य कार्य की न्यायपूर्ण और मानवीय स्थितियों को सुरक्षित करने और प्रसूति राहत के लिए प्रावधान करेगा।

62 अनुच्छेद 51 (ए): (ई)। यह भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि वह महिलाओं की गरिमा के लिए अपमानजनक प्रथाओं का त्याग करे। 63 महिलाओं के खिलाफ सभी प्रकार के भेदभाव के उन्मूलन पर समझौता

64 संक्षेप में 'पॉश एक्ट'

65 (2013) 1 एससीसी 311 [2023] 7 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

नियम "। एक समान संशोधन को भी लागू करने का निर्देश दिया गया था

परीक्षण रोजगार (स्थायी आदेश) नियम।

50. 17 जनवरी, 2006 को मेधा कोतवाल के मामले में भी ऐसा ही हुआ था

6 , ध्यान दें कि इसके बारे में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं थी विशाखा के मामले (ऊपर) में जारी किए गए निर्देशों का प्रतिपादन, यह

उन्होंने निम्नलिखित दिशाओं का अनुसरण किया:

" 2. यह ज्ञात नहीं है कि क्या समितियों ने सुझाव दिया है विशाखा के मामले में 50 और उससे अधिक के कर्मचारियों वाले सभी विभागों/संस्थानों में गठन किया गया है और सभी राज्यों में अधिकांश जिला स्तरीय कार्यालयों में कुछ कार्यालयों में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या 50 से अधिक होगी। यह ज्ञात नहीं है कि विशाखा मामले में परिकल्पित समितियों का गठन इन सभी कार्यालयों में किया गया है या नहीं। प्राप्त शिकायतों की संख्या और इन शिकायतों में उठाए गए कदम भी उपलब्ध नहीं हैं। हम इस संबंध में कुछ और निर्देश देना आवश्यक समझते हैं:

2.1 . हम पाते हैं कि इस संबंध में उठाए गए कदमों का समन्वय करने के लिए राज्य स्तर का एक अधिकारी होना चाहिए अर्थात् महिला और बाल कल्याण विभाग का सचिव या कोई अन्य उपयुक्त अधिकारी जो प्रत्येक राज्य में महिलाओं और बच्चों के कल्याण का प्रभारी और संबंधित हो। प्रत्येक राज्य के मुख्य सचिव देखेंगे कि विवरण एकत्र करने और जब भी आवश्यक हो उपयुक्त निर्देश देने के लिए एक अधिकारी को नोडल एजेंट के रूप में नियुक्त किया जाता है।

2.2 . कारखानों, दुकानों और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के संबंध में, निर्देशों का पूरी तरह से पालन नहीं किया जाता है। द. प्रत्येक राज्य के श्रम आयुक्त इस दिशा में कदम उठाएंगे।

दिशा। वे दुकानों के संबंध में नोडल एजेंसी के रूप में काम करेंगे।
प्रतिष्ठानों का संबंध है। वे.

कारखानों और वाणिज्यिक

3) 1 एस. सी. सी. 312 ऑरिलियानो फर्नांडीस बनाम। गोवा राज्य और अन्य [हिमा कोहली, जे.]

शिकायतों के संबंध में विवरण भी एकत्र करेगा और यह भी देखेगा कि ऐसी संस्थाओं में आवश्यक समिति स्थापित की गई है।

51. आदेश जारी रखने की अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उपरोक्त याचिका पर छह साल से अधिक समय बीतने के बाद, 19 अक्टूबर, 2012 को फिर से विचार किया गया, जब इस न्यायालय ने प्रत्येक राज्य सरकार द्वारा दायर हलफनामों की जांच की ताकि इन नियमों के अनुपालन पर खुद को संतुष्ट किया जा सके।

विशाखा के मामले में निर्धारित दिशानिर्देश (ऊपर)। में किए जाने वाले आवश्यक संशोधनों के संबंध में स्थिति की जांच करने पर

सी. सी. एस. (सी. सी. ए.) नियम और स्थायी आदेशों के साथ-साथ शिकायत समितियों की स्थापना और संरचना, न्यायालय ने बड़ी निराशा के साथ कहा कि कई राज्य सरकारें ऐसा करने में विफल रही हैं

अनुपालन। इस संबंध में की गई टिप्पणियाँ नीचे उद्धृत की गई हैं:

" 43. दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में हमें महिलाओं के खिलाफ हिंसा का मुकाबला करना है। हमारा विचार है कि यदि आवश्यक हो तो मौजूदा कानूनों को संशोधित किया जाए और सुरक्षा के लिए संसद और राज्य विधानमंडलों द्वारा उपयुक्त नए कानून बनाए जाएं। सभी स्थानों पर (अपने घरों के साथ-साथ बाहर) किसी भी प्रकार की अभद्रता, अपमान और अनादर से महिलाएं, सभी प्रकार की हिंसा घरेलू हिंसा, यौन उत्पीड़न, यौन उत्पीड़न को रोकती हैं।

कार्यस्थल आदि पर और जीवन के सभी क्षेत्रों में महिलाओं और लड़कियों की शिक्षा और उन्नति के लिए नई पहल प्रदान करना। आखिरकार उनके पास असीम क्षमता है। अभद्र भाषा, खोखले बयान और अव्यवस्थित प्रवर्तन के साथ निष्क्रिय और अपर्याप्त कानून हमारे आधे सबसे कीमती के सच्चे और वास्तविक उत्थान के लिए पर्याप्त नहीं हैं।

जनसंख्या-महिलाएँ।

44. हमने ऊपर जो चर्चा की है, उसमें हमारा विचार है कि विशाखा में दिशा-निर्देश प्रतीकात्मक नहीं रहने चाहिए और विधायी होने तक निम्नलिखित आगे के निर्देश आवश्यक हैं।

इस विषय पर अधिनियम लागू है:

44.1 . जिन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने अभी तक अपने संबंधित सिविल सेवा आचरण नियमों (चाहे इन नियमों को किसी भी नाम से जाना जाए) में पर्याप्त और उचित संशोधन नहीं किए हैं, वे आज से दो महीने के भीतर यह प्रावधान करेंगे कि शिकायत समिति की रिपोर्ट को ऐसी सिविल सेवाओं के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई में एक जांच रिपोर्ट माना जाएगा।

नियमों का पालन करें। दूसरे शब्दों में, अनुशासनात्मक प्राधिकारी

67 (2013) 1 एस. सी. सी. 297 [2023] 7 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

शिकायत समिति की रिपोर्ट/निष्कर्षों आदि को अपराधी कर्मचारी के खिलाफ अनुशासनात्मक जांच में निष्कर्षों के रूप में माना जाएगा और तदनुसार ऐसी रिपोर्ट पर कार्रवाई की जाएगी। शिकायत समिति के निष्कर्षों और रिपोर्ट को केवल प्रारंभिक जांच या अनुशासनात्मक कार्रवाई की ओर ले जाने वाली जांच के रूप में नहीं माना जाएगा, बल्कि अपराधी के कदाचार की जांच में एक निष्कर्ष/रिपोर्ट के रूप में माना जाएगा।

44.2 . जिन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने औद्योगिक रोजगार (स्थायी आदेश) में संशोधन नहीं किए हैं

नियम अब दो महीने के भीतर उसी तर्ज पर संशोधन करेंगे, जैसा कि पैरा 44.1 में ऊपर उल्लेख किया गया है।

44.4 . राज्य के पदाधिकारी और निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/संगठन/निकाय/संस्थान आदि विशाखा के पूर्ण कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त तंत्र स्थापित करेंगे। दिशानिर्देश और आगे यह प्रावधान है कि यदि कथित उत्पीड़क दोषी पाया जाता है, तो शिकायतकर्ता पीड़ित को ऐसे उत्पीड़क के साथ/उसके तहत काम करने के लिए मजबूर नहीं किया जाता है और जहां उपयुक्त और संभव हो, कथित उत्पीड़क का स्थानांतरण किया जाना चाहिए। इसके अलावा यह प्रावधान किया जाना चाहिए कि गवाहों और शिकायतकर्ताओं को परेशान करने और डराने-धमकाने के लिए गंभीर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

44.5 . बार काउंसिल ऑफ इंडिया यह सुनिश्चित करेगी कि देश के सभी बार एसोसिएशन और राज्य बार काउंसिल में पंजीकृत व्यक्ति विशाखा दिशानिर्देशों का पालन करें। इसी तरह, भारतीय चिकित्सा परिषद, वास्तुकला परिषद, सनदी लेखाकार संस्थान,

कंपनी सचिव संस्थान और अन्य वैधानिक संस्थान यह सुनिश्चित करेंगे कि संगठन, निकाय, संघ, संस्थान और उनके साथ पंजीकृत/संबद्ध व्यक्ति विशाखा द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों का पालन करें। इसे प्राप्त करने के लिए, आवश्यक निर्देश/ऑरेलियानो फर्नांडीस V.

गोवा राज्य और अन्य [हिमा कोहली, जे.]

भारतीय विधिज्ञ परिषद, भारतीय चिकित्सा परिषद, भारतीय विधिज्ञ परिषद जैसे सभी वैधानिक निकायों द्वारा परिपत्र जारी किए जाएंगे।

वास्तुकला, कंपनी सचिव संस्थान आज से दो महीने के भीतर। ऊपर निर्दिष्ट किसी भी स्थान पर यौन उत्पीड़न की कोई भी शिकायत प्राप्त होने पर वैधानिक निकायों द्वारा विशाखा और अन्य के अनुसार निपटा जाएगा। राजस्थान राज्य और अन्य (1997) 6 एससीसी 241, दिशानिर्देश

और वर्तमान क्रम में दिशानिर्देश "।

(ग) सकारात्मक अधिनियम और नियमों की स्थापना:

52. विशाखा के मामले (ऊपर) में दिए गए फैसले की तारीख से पंद्रह साल बीतने के बाद, पाँच अधिनियम, पर कानून बनाया गया था

22 अप्रैल, 2013 और अंत में 9 दिसंबर, 2013 को अधिसूचित किया गया। इस अधिनियम में आंतरिक शिकायत समिति, स्थानीय समिति और आंतरिक समितियों के गठन, प्राप्त शिकायत की जांच करने का तरीका, नियोक्ता के कर्तव्य, जिला अधिकारी और अन्य के कर्तव्य और शक्तियां, अधिनियम के प्रावधानों का पालन न करने के लिए दंड आदि के लिए एक व्यापक तंत्र निर्धारित किया गया है। अधिनियम के साथ नियम, 201368 हैं जो पी. ओ. एस. एच. अधिनियम की धारा 29 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाए गए हैं और अन्य बातों के अलावा, यौन उत्पीड़न की शिकायत की जांच करने का तरीका (नियम 7), जांच लंबित रहने के दौरान पीड़ित महिलाओं को दी जा सकने वाली अंतरिम राहत (नियम 8), यौन उत्पीड़न के लिए कार्रवाई करने का तरीका (नियम 9) आदि निर्धारित करते हैं। यह उल्लेखनीय है कि नियम 7 के उप-नियम (3) में यह प्रावधान है कि प्रतिवादी संबंधित दस्तावेजों के साथ एक निर्धारित समय के भीतर शिकायत पर अपना जवाब दाखिल करेगा और गवाहों का विवरण देगा और उप-नियम (4) में कहा गया है कि शिकायत समिति "प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुसार" शिकायतों की जांच करेगी।

(घ) श्वास अंदर आने का कारण

प्रक्रियात्मक नियम:

53. इस प्रकार, यह देखा जा सकता है कि विशाखा के मामले (उपरोक्त) से यात्रा जिसने एक स्पिंगबोर्ड के रूप में काम किया और भविष्य के बीज बोए

यौन उत्पीड़न के मामलों से निपटने के लिए दिशानिर्देशों की संरचना करके कानून, एक व्यापक कानून के रूप में विकसित हुआ

पी. ओ. एस. एच. अधिनियम और नियमों को लागू करना। लेकिन साथ ही,

68 कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 [2023] 7 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

महिला केंद्रित दिशानिर्देश और अधिनियम भले ही रहे हों, वे दोनों इस तथ्य को स्वीकार करते हैं कि कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की शिकायत की कोई भी जांच प्रासंगिक नियमों के अनुसार और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुरूप होनी चाहिए। इस मुख्य सिद्धांत को ध्यान में रखने की आवश्यकता है कि दुराचार के आरोपी व्यक्ति को मामले के बारे में सूचित किया जाना चाहिए, उसके समर्थन में सबूत दिए जाने चाहिए और कोई भी प्रतिकूल निर्णय लेने से पहले उसे अपना पक्ष रखने का उचित अवसर दिया जाना चाहिए। इसी तरह, संबंधित नियोक्ता से भी निष्पक्ष रूप से कार्य करने और एक ऐसी प्रक्रिया अपनाने की अपेक्षा की जाती है जो न्यायपूर्ण, निष्पक्ष और उचित हो। पूरा उद्देश्य प्रक्रियात्मक व्यवस्था में तर्कसंगतता की सांस लेना है। लेकिन, तर्कसंगतता की परीक्षा अमूर्त नहीं हो सकती है। इसे व्यावहारिक होना चाहिए और किसी मामले के तथ्यों और परिस्थितियों की वास्तविकताओं पर आधारित होना चाहिए। जाँच करते समय, यह जाँच प्राधिकरण का कर्तव्य है कि वह इस तरह से आगे बढ़े जो स्पष्ट रूप से मनमानेपन, अनुचितता या अन्याय के दाग से मुक्त हो। एक जांच जो एक कर्मचारी की सेवा की समाप्ति जैसे बड़े जुर्माने के अधिरोपण में परिणत हो सकती है, उसे एक न्यायपूर्ण, निष्पक्ष और उचित प्रक्रिया के लिए दोगुना अनुरूप होना चाहिए। प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का कोई भी विस्थापन केवल असाधारण परिस्थितियों में ही हो सकता है, जैसा कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 311 (2) के प्रावधान में विचार किया गया है और अन्यथा नहीं। जहां भी नियम मौन हैं, उनमें प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों को पढ़ा जाना चाहिए और उस व्यक्ति को सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिए जिसे एक बड़े दंड से दंडित करने का प्रस्ताव है।

54. चार प्रमुख उद्देश्यों को प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों को कानून में पढ़कर और इसके संचालन में प्राप्त करने की मांग की गई

निष्पक्षता प्राप्त करने के अंतर्निहित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए न्यायिक और प्रशासनिक कार्यवाहियों को इस न्यायालय द्वारा प्रक्रियात्मक नियमों, कार्यवाहियों में समानता के आश्वासन, निर्णय और निर्णय लेने के अधिकार का पालन करके एक निष्पक्ष परिणाम के आश्वासन के रूप में संक्षिप्त रूप से व्यक्त किया गया है, जिससे प्रणाली की अखंडता को संरक्षित किया जाता है और अंत में, व्यक्तियों की गरिमा को संरक्षित करने के विचार के साथ जहां नागरिकों के साथ कानून के शासन द्वारा शासित समाज में सम्मान और गरिमा के साथ व्यवहार किया जाता है।

एल. विश्लेषण और विवेचना:

55. वर्तमान मामले में, विचाराधीन घटनाएं संबंधित हैं

69

भारतीय स्टेट बैंक और अन्य बनाम। रंजीत कुमार चक्रवर्ती और एक अन्य, (2018) 12 एस. सी. सी. 807

70 मध्यमम ब्रॉडकास्टिंग लिमिटेड बनाम भारत संघ ने 5 अप्रैल 2023 को ऑरिलियानो फर्नांडीस बनाम.

गोवा राज्य और अन्य [हिमा कोहली, जे.]

उस अवधि में जब विशाखा दिशानिर्देश लागू थे और मेधा कोतवाल लेल (ऊपर) में यह स्पष्ट किया गया था कि शिकायत समिति को सी. सी. एस. के उद्देश्यों के लिए एक जांच प्राधिकरण माना जाएगा। नियम। इसे ध्यान में रखते हुए, अब हम यह पता लगाने के लिए आगे बढ़ सकते हैं कि क्या उत्तरदाता संख्या 2 और 3 द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया ने प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन किया है और इस तरह अपीलार्थी के लिए पूर्वाग्रह पैदा किया है, जैसा कि आरोप लगाया गया है, कि इस न्यायालय ने विवादित निर्णय में हस्तक्षेप किया है।

(क) उच्च न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप का दायरा

न्यायिक समीक्षा में:

56. शुरुआत में यह स्पष्ट किया जा सकता है कि खुद को संतुष्ट करने के लिए कि अपीलार्थी के साथ कोई अन्याय नहीं किया गया है, उच्च न्यायालय को निर्णय लेने की प्रक्रिया की जांच करने की आवश्यकता थी, न कि केवल अंतिम परिणाम की। दूसरे शब्दों में, न्यायिक समीक्षा की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय विभागीय कार्यवाहियों में दर्ज तथ्यात्मक निष्कर्षों पर एक अपीलीय प्राधिकरण के रूप में तब तक नहीं बैठता है जब तक कि वे निष्कर्ष साक्ष्य द्वारा उचित रूप से समर्थित हैं और उन कार्यवाहियों के माध्यम से पहुंचे हैं जिन्हें प्रक्रियात्मक अवैधताओं या अनियमितताओं के कारण दोष नहीं दिया जा सकता है।

हो सकता है कि इसने उस प्रक्रिया को दूषित कर दिया हो जिसके द्वारा निर्णय लिया गया था। 57. न्यायिक समीक्षा का उद्देश्य न केवल यह सुनिश्चित करना है कि संबंधित व्यक्ति को उचित व्यवहार मिले, बल्कि यह भी सुनिश्चित करना है कि प्राधिकरण, उचित व्यवहार के बाद, एक निष्कर्ष पर पहुंचे, जो कानून की दृष्टि में सही है। विशेष रूप से, परिधान निर्यात संवर्धन में

परिषद बनाम। ए. के. चोपड़ा, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से संबंधित मामला 1 2 जहां अनुशासनात्मक प्राधिकरण द्वारा जांच अधिकारी की रिपोर्ट को स्वीकार करने और प्रतिवादी को इस आधार पर सेवा से हटाने के निर्णय से व्यथित है कि उसने एक महिला कर्मचारी से छेड़छाड़ करने की कोशिश की थी, इस न्यायालय ने उच्च न्यायालय के उस आदेश को दरकिनार कर दिया था जिसमें "यौन उत्पीड़न" अभिव्यक्ति की संकीर्ण व्याख्या की गई थी और कहा गया था कि विभागीय कार्यवाही में अनुशासनात्मक प्राधिकरण तथ्यों का एकमात्र न्यायाधीश है और एक बार तथ्य के निष्कर्ष, साक्ष्य की सराहना के आधार पर दर्ज किए जाने के बाद, उच्च न्यायालय को अपने रिट क्षेत्राधिकार में आम तौर पर उन तथ्यात्मक निष्कर्षों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए जब तक कि यह न पाया जाए कि दर्ज किए गए निष्कर्ष या तो किसी सबूत पर आधारित थे या निष्कर्ष पूरी तरह से विकृत और/या कानूनी थे। न्यायालय एक के अधीन है 71 (1999) 1 एस. सी. सी. 759 72 नॉर्थ वेल्स पुलिस के मुख्य कांस्टेबल बनाम। इवांस, (1982) 3 ऑल ईआर 141 एचएल। यह भी देखें - बी. सी. चतुर्वेदी बनाम भारत संघ, (1995) 6 एस. सी. सी. 749।

23] 7 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

स्वयं को संतुष्ट करना कर्तव्य है कि एक समिति द्वारा यौन उत्पीड़न के आरोपों की जांच सेवा नियमों के संदर्भ में की जाती है और संबंधित कर्मचारी को एक उचित अवसर मिलता है

अपनी स्थिति को सही साबित करें और अपनी बेगुनाही स्थापित करें।

व्यावहारिक "नॉर्म"

58. सही मानते हुए, विद्वान वकील द्वारा प्रस्तुत किया गया निवेदन

उत्तरदाताओं के लिए नहीं। 2 और 3 कि समिति सी. सी. एस. (सी. सी. ए.) नियमों के नियम 14 (2) के प्रावधान को ध्यान में रखते हुए जांच करने के लिए चरण-दर-चरण प्रक्रिया का सख्ती से पालन करने के लिए बाध्य नहीं थी, जो एक समिति को नियमों में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार 'जहां तक संभव हो' यौन उत्पीड़न की शिकायत की जांच करने की अनुमति देती है, फिर भी जिस प्रश्न का उत्तर मिलना चाहिए वह यह है कि क्या समिति द्वारा तत्काल मामले में की गई जांच 'जहां तक संभव हो' मानदंड को पूरा करेगी?

59. नियम 14 एक सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा जांच करने के लिए आवश्यक प्रक्रिया निर्धारित करता है जिसमें एक

आरोप पत्र, आरोप के अनुच्छेदों का विवरण प्रस्तुत करना, संलग्न करना

आरोप के प्रत्येक लेख के संबंध में आरोप के बयान, गवाहों की एक सूची और प्रबंधन/नियोक्ता द्वारा भरोसा किए जाने वाले दस्तावेजों को अग्रेषित करना। हो सकता है कि समिति ने वर्तमान मामले में उक्त प्रक्रिया का सख्ती से पालन न किया हो, लेकिन यह विवाद में नहीं है कि समय-समय पर प्राप्त सभी शिकायतों और शिकायतकर्ताओं के बयानों का खुलासा अपीलार्थी को किया गया था। इसलिए, वह अपने खिलाफ लगाए गए आरोपों की प्रकृति से अच्छी तरह वाकिफ थे। न केवल उन्हें दी गई जांच के दौरान उनके खिलाफ प्रस्तावित सामग्री का उपयोग किया गया था, बल्कि उन्हें अपना जवाब प्रस्तुत करके और गवाहों की एक सूची प्रस्तुत करके उक्त सामग्री को समझाने के लिए भी कहा गया था, जो उन्होंने किया। इसके अलावा, समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने पर, यह स्पष्ट होता है कि कुछ शिकायतकर्ताओं के बयानों को समिति द्वारा ऑडियो-विजुअली रिकॉर्ड किया गया था, जहां भी सहमति दी गई थी और अपीलकर्ता को शिकायतकर्ताओं सहित उक्त गवाहों से जिरह करने का अवसर दिया गया था। सभी शिकायतकर्ताओं द्वारा लगाए गए आरोप अपीलार्थी द्वारा विशिष्ट उदाहरणों के विवरण के साथ यौन उत्पीड़न के थे। इसलिए, दिए गए तथ्यों और परिस्थितियों में, समिति द्वारा प्रभार के अनुच्छेदों को न बनाए जाने को माना नहीं जा सकता है।

73 डॉ. विजयकुमारन सी. पी. वी. बनाम केरल केंद्रीय विश्वविद्यालय और अन्य, (2020) 12 एस. सी. सी. 426 ऑरिलियानो फर्नांडिस बनाम।

गोवा राज्य और अन्य [हिमा कोहली, जे.]

घातक। न ही अपीलार्थी को यह कहते हुए सुना जा सकता है कि वह अपने खिलाफ लगाए गए आरोपों की प्रकृति के बारे में पूरी तरह से अंधेरे में था और उचित रूप से जवाब देने की स्थिति में नहीं था। अब तक, इतना अच्छा।

(ग) समिति की अपनी स्थिति को समझना।

अनिवार्य:

60. जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, जब प्रत्यर्थी संख्या 2 विश्वविद्यालय के कुलसचिव ने समिति के अध्यक्ष को एक पत्र संबोधित किया, तो उन्होंने

विश्वविद्यालय के कुलपति को यौन उत्पीड़न की नौ शिकायतें मिली थीं। जाँच की प्रक्रिया 17 मार्च 2009 को शुरू की गई थी जब अपीलार्थी को सूचित किया गया था कि उसके खिलाफ यौन उत्पीड़न की शिकायतें मिलने पर समिति ने संबंधित छात्रों के बयान दर्ज करके शिकायतों का प्रारंभिक सत्यापन किया था। तब तक, समिति द्वारा कोई विशिष्ट आरोप अनुच्छेद तैयार नहीं किया गया था और अपीलार्थी को किसी भी आरोप का आरोप नहीं भेजा गया था। साथ ही, प्राप्त सभी शिकायतों और दर्ज किए गए बयानों की प्रतियां सीधे अपीलार्थी को भेज दी गईं और उससे अपने खिलाफ लगाए गए आरोपों की व्याख्या करने के लिए कहा गया।

61. अपीलार्थी की याचिका कि समिति ने अपनी जांच के प्रेषण को 'तथ्य-खोज कार्यवाही' के रूप में समझा, अपीलार्थी को संबोधित 17 मार्च 2009 और 20 अप्रैल 2009 के पत्रों की सामग्री से समझा जा सकता है। समिति द्वारा लिया गया प्रभाव

यह कि विश्वविद्यालय को केवल एक तथ्य-निष्कर्ष रिपोर्ट प्रस्तुत करने की आवश्यकता थी, निर्वाचन आयोग के लिए अलग नहीं था जैसा कि विश्वविद्यालय के एक अवलोकन से पता चलता है।

निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष द्वारा 8 सितंबर 2009 को जारी ज्ञापन, जिन्होंने समिति की रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद अपीलार्थी को सूचित किया कि नियम 14 के तहत उनके खिलाफ जांच करने का प्रस्ताव है।

सीसीएस (सीसीए) नियम। यह पहली बार था जब प्रत्यर्थियों ने अपीलार्थी को सूचित किया कि निर्वाचन आयोग ने आरोप के अनुच्छेदों का विवरण तैयार करने, आरोप के प्रत्येक अनुच्छेदों और अन्य दस्तावेजों के समर्थन में कदाचार के आरोप लगाने के नियमों के तहत निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने का फैसला किया था और अपीलार्थी को बचाव में अपना जवाब प्रस्तुत करने के लिए समय दिया था। अपीलार्थी ने जवाब प्रस्तुत किया। लेकिन यह एक स्वीकृत स्थिति है कि उक्त जांच कार्यवाही को प्रारंभिक चरण में ही निरस्त कर दिया गया था और यह पहले प्रस्तुत की गई समिति की रिपोर्ट थी, जिस पर चुनाव आयोग ने 28 जनवरी 2010 को लिए गए निर्णय के संदर्भ में कार्रवाई की थी। हमारी राय है कि जब समिति स्वयं अपनी जांच के दायरे के बारे में अस्पष्ट थी, तो अपीलार्थी को [2023] 7 एस. सी. आर. को आश्रय देने के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

यह धारणा कि समिति का प्रेषण केवल तथ्य खोजने तक ही सीमित था और यह सेवा नियमों के तहत अनुशासनात्मक समिति के कार्यों का निर्वहन नहीं कर रहा था।

(घ) सफेद प्रक्रियाएँ

62. अभिलेखों की जांच करने पर यह पता चलता है कि किस बिंदु पर

समिति एक त्रुटि में पड़ गई जब उसने पहली कुछ सुनवाई के बाद पूरी कार्यवाही को तेजी से आगे बढ़ाने का प्रयास किया और अपीलार्थी को उक्त कार्यवाही में प्रभावी ढंग से भाग लेने के लिए उचित समय देने से इनकार कर दिया। उल्लेखनीय है कि समिति की कार्यवाही यह 16 अप्रैल, 2009 को शुरू हुआ था और 5 जून, 2009 को समाप्त हुआ था। इस अवधि के दौरान समिति द्वारा 18 बैठकें आयोजित की गईं। समिति की बैठकें जिन तिथियों पर आयोजित की गईं, उनका माहवार विवरण निम्नलिखित है:

(i) अप्रैल 2009-16, 27 और 29 तारीख को
(ii) मई 2009-6, 12, 13, 14, 19, 20, 22, 23, 25, 27, 28 तारीख को

और 29 वां

(iii) जून, 2009-3, 4 और 5 तारीख को
63. यह भी उल्लेखनीय है कि इसके तहत निर्धारित समय अवधि

जांच समाप्त करने के लिए सी. सी. एस. (सी. सी. ए.) नियम आमतौर पर नियुक्ति के आदेश की प्राप्ति की तारीख से छह महीने की अवधि के भीतर होते हैं। लेकिन,

यहाँ, पूरी प्रक्रिया को 39 दिनों में पूरा किया गया था। यह समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने की तीव्र जल्दबाजी को दर्शाता है। कार्यवाही को समाप्त करने के लिए अत्यधिक चिंता का एक ऐसा स्पष्ट उदाहरण 5 मई 2009 के पत्र से स्पष्ट है, जिसे समिति द्वारा अपीलार्थी को संबोधित किया गया था, जिसमें उन्हें सूचित किया गया था कि उनका जवाब दाखिल करने और आगे के बयान दर्ज करने की अगली तारीख 12 जून 2009 थी। आश्चर्य की बात यह है कि समिति ने अगले ही दिन उक्त तिथियों को आगे बढ़ाते हुए एक और पत्र जारी किया जिसमें दावा किया गया कि पिछले पत्र में एक त्रुटि आई है और अपीलार्थी को सूचित किया गया है कि उसका जवाब दाखिल करने की तारीख को '12 मई 2009' के रूप में पढ़ा जाना चाहिए और आगे के बयान दर्ज करने की तारीख को '14 मई, 2009' के रूप में पढ़ा जाना चाहिए, इस प्रकार तारीखों को पूरे एक महीने के लिए आगे बढ़ाया जाना चाहिए। द्वारा दिखाई गई जल्दबाजी और हड़बड़ी का एक और गंभीर उदाहरण

समिति को इस तथ्य से एकत्र किया जा सकता है कि 20 मई 2009 को समिति ने अपीलार्थी को पत्र लिखकर उसे अंतिम अवसर दिया था -

20 मई 2009 को न केवल अपना बयान पूरा करने के लिए, बल्कि शिकायतकर्ताओं और अन्य गवाहों से जिरह करने के लिए भी खुद को पेश करें। इसके साथ ही, समिति ने ऑरिलियानो फर्नंडिस बनाम को छह और बयान भेजे।

गोवा राज्य और अन्य [हिमा कोहली, जे.]

अपीलार्थी ने उन्हें 48 घंटे के भीतर यानी 22 मई, 2009 तक अपना जवाब देने का निर्देश दिया।

64. भले ही इस न्यायालय को प्रत्यर्थियों के लिए विद्वान वकील द्वारा की गई प्रस्तुति को स्वीकार करना था कि अपीलार्थी कमजोर पेशकश कर रहा था

कार्यवाही और स्वास्थ्य आधार को किसी तरह बढ़ाने के लिए बहाना उनके द्वारा लिया गया बयान वास्तविक नहीं था, यह समिति के दृष्टिकोण की व्याख्या नहीं करता है जो इस तथ्य से अच्छी तरह वाकिफ थी कि 20 मई 2009 को अपीलार्थी को कम से कम छह और बयान सौंपे गए थे। भले ही वह शांत और दयालु होता, फिर भी उसे अतिरिक्त बयानों का जवाब देने के लिए एक उचित समय की आवश्यकता होती और

साथ ही, शिकायतकर्ताओं से जिरह करने के लिए खुद को तैयार करें और अपने बयान को पूरा करना। समिति द्वारा इसे केवल अनुचित और अनुचित निर्देश ही कहा जा सकता है।

65. जांच को बंद करने के लिए समिति द्वारा दिखाई गई अनुचित जल्दबाजी, आयोग के अधिकार में कटौती को उचित नहीं ठहरा सकती है। निष्पक्ष सुनवाई के लिए अपीलार्थी। उचित प्रक्रिया, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का एक महत्वपूर्ण पहलू, समिति द्वारा जांच करने के तरीके के कारण गंभीर रूप से समझौता किया गया था।

कार्यवाही। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, जब वर्तमान अपील की कार्यवाही, विषय वस्तु हुई थी, तो पी. ओ. एस. एच. अधिनियम कहीं भी क्षितिज पर नहीं था और क्षेत्र पर विशाखा दिशानिर्देशों का कब्जा था। उक्त दिशानिर्देशों में प्रक्रियात्मक अनुपालन करने में प्राकृतिक न्याय और निष्पक्षता के सिद्धांतों के अनुप्रयोग को भी शामिल नहीं किया गया है। इस पहलू पर दिशा-निर्देशों में मौन समिति को प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों को दरकिनार करने और अपीलार्थी को निष्पक्ष सुनवाई देने के उचित अवसर को कम करने के लिए एक नियंत्रण नहीं दे सकता था। इस न्यायालय ने बार-बार कहा है कि जब नियम मौन हैं, तब भी उनमें प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों को पढ़ा जाना चाहिए। पीड़ितों/शिकायतकर्ताओं के प्रति निष्पक्ष होने और शिकायतों को समाप्त करने की अपनी गहरी चिंता में

शीघ्रता से, समिति अपीलार्थी के प्रति घोर रूप से अनुचित साबित हुई है। इसने इस मूल सिद्धांत की पूरी तरह से अनदेखी की है कि न्याय न केवल किया जाना चाहिए, बल्कि स्पष्ट रूप से किया जाता दिखना चाहिए। ऑडी अल्टरम पार्टेम के सिद्धांतों को इस तरह से हवा में नहीं फेंका जा सकता था।

(ड) कार्यकारी परिषद का पतन कैसे हुआ?

66. निर्वाचन आयोग की ओर से की गई गलती भी कम गंभीर नहीं है। यह स्पष्ट है कि ई. सी. इस धारणा के तहत बना रहा कि

पहली समिति जिसे शिकायतें भेजी गई थीं, केवल एक [2023] 7 एस. सी. आर. थी।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

'तथ्य-खोज समिति' और यह कि सी. सी. एस. (सी. सी. ए.) नियमों के नियम 14 के तहत निर्धारित तरीके से बाद में एक पूर्ण जांच की आवश्यकता थी। परिणाम यह हुआ कि हालांकि पहली समिति की रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया गया और चुनाव आयोग ने

निलंबन के तहत अपीलार्थी, पहली बार, उसे आरोप के अनुच्छेदों और के आरोप का विवरण देते हुए ज्ञापन जारी करने का निर्णय लिया

कोतवाल के मामले में जहां इस न्यायालय द्वारा यह स्पष्ट किया गया था कि विशाखा के मामले (उपरोक्त) में विचार की गई शिकायत समिति को सी. सी. एस. (आचरण) नियमों के प्रयोजनों के लिए एक जांच प्राधिकरण माना जाएगा और इसकी रिपोर्ट को सी. सी. एस. (सी. सी. ए.) नियमों के तहत एक रिपोर्ट माना जाएगा।

67. जब नियोक्ता स्वयं समिति के प्रेषण से अनजान था और समिति अपनी कार्यवाही को तथ्य-निष्कर्ष प्रकृति के रूप में वर्णित करने के बाद उसी धारणा के तहत बनी रही, तो उत्तरदाताओं के लिए यह और भी अधिक आवश्यक था कि वे पहली समिति की रिपोर्ट प्राप्त करने पर रुकें और अगला कदम उठाने से पहले कानूनी स्थिति का सत्यापन करें। इन सब में, यह यौन उत्पीड़न की जांच करने के लिए नियम 14 के तहत निर्धारित प्रक्रिया थी।

कार्यस्थल जिसे शीघ्र निपटान के परिवर्तन पर त्याग दिया गया था, जिसे न तो उचित ठहराया जा सकता है और न ही स्वीकार किया जा सकता है।

68. सी. सी. एस. (सी. सी. ए.) नियमों के नियम 14 (2) और सी. सी. एस. (आचरण) नियमों के नियम 3 सी में अंतःस्थापित परंतुक का आशय और उद्देश्य यह है कि - यौन उत्पीड़न की शिकायत की जांच करने के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया जो नियमों के तहत एक बड़ा जुर्माना लगा सकती है, निष्पक्ष, निष्पक्ष और नियमों के अनुरूप होनी चाहिए। उल्लेखनीय है कि शिकायत समिति द्वारा की गई जांच के दौरान प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करने पर जोर देने का बाद में 2013 के अधिनियमित नियमों के नियम 7 (4) में विशिष्ट उल्लेख मिलता है। लेकिन कानून या नियमों के अभाव में भी उचित प्रक्रिया के पीछे की भावना को कभी दबाया या नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था क्योंकि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत निर्णय लेने की प्रक्रिया का सार हैं और इन्हें प्रत्येक न्यायिक या अर्ध-न्यायिक कार्यवाही में भी पढ़ा जाना चाहिए।

69. यह कहना नहीं है कि समिति भले ही एक जांच प्राधिकरण के रूप में वर्णित हो, मेधा कोतवाल के मामले (ऊपर) में निर्णय के आधार पर और नियम 14 के तहत निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने के लिए आवश्यक हो, ऑरिलियानो फर्नांडीस बनाम था।

गोवा राज्य और अन्य [हिमा कोहली, जे.]

उनसे अपेक्षा की जाती थी कि वे जाँच का संचालन करें जैसे कि यह एक पूर्ण-स्तरीय मुकदमा हो। नियम 14 (2) के परंतुक में प्रयुक्त अभिव्यक्ति, 'जहाँ तक व्यावहारिक हो' को व्यावहारिक तरीके से पढ़ना और समझना होगा। ऐसे किसी भी मामले में

अनुशासनात्मक प्राधिकरण द्वारा शुरू की गई कार्यवाहियों में यौन उत्पीड़न की शिकार महिला और अपराधी कर्मचारी के अधिकारों के बीच एक संतुलित संतुलन स्थापित करना होगा। साथ ही, दोनों पक्षों के हित में प्रक्रिया में निष्पक्षता को अनिवार्य रूप से अपनाना होगा। आखिरकार, हंस के लिए जो चटनी है, वह गैंडर के लिए चटनी है।

एम. कन्क्लूजन

70. तत्काल मामले में, हालांकि अनुशासनात्मक प्राधिकरण द्वारा नियुक्त समिति ने सी. सी. एस. (सी. सी. ए.) नियमों के नियम 14 में निर्धारित चरण-दर-चरण प्रक्रिया के संदर्भ में सख्ती से जांच नहीं की, फिर भी, हमने देखा है कि उसने सभी शिकायतों की प्रतियां, शिकायतकर्ताओं के बयान और संबंधित सामग्री प्रस्तुत की।

अपीलार्थी ने उसे बचाव में अपना जवाब देने के लिए कहा और उसे निर्देश दिया

गवाहों की सूची प्रस्तुत करने के लिए जिन पर उन्होंने भरोसा करने का प्रस्ताव रखा। अभिलेखों से यह भी पता चलता है कि अपीलार्थी ने बचाव में एक विस्तृत जवाब दिया था। उन्होंने गवाहों और बयानों की एक सूची भी प्रस्तुत की थी। इससे पता चलता है कि वह अपने खिलाफ लगाए गए आरोपों की प्रकृति से अच्छी तरह से परिचित था और जानता था कि उसे अपने बचाव में क्या कहना है। उपरोक्त स्थिति को देखते हुए, आरोप के लेखों को न तैयार करना अपीलार्थी के हित के लिए हानिकारक नहीं कहा जा सकता है।

71. वास्तव में, जांच की कार्यवाही में स्पष्ट दोष और प्रक्रियात्मक खामियां उसके बाद ही मई के महीने में हुईं।

2009 , जब 12 सुनवाई हुई, उनमें से अधिकांश एक के बाद एक, समिति द्वारा तेज गति से आयोजित की गईं। एक ओर समिति अपीलार्थी को कुछ और बयान भेजती रही।

शिकायतकर्ताओं ने बाद में और अन्य गवाहों के गवाहों को प्राप्त किया और उन्हें अपना जवाब देने के लिए कहा और दूसरी ओर, इसने उन्हें निर्देश दिया कि वे उक्त शिकायतकर्ताओं और गवाहों से जिरह करने के लिए तैयार रहें और साथ ही एक सप्ताह की अवधि में अपनी आगे की गवाही भी दर्ज करें। भले ही अपीलार्थी द्वारा लिए गए चिकित्सीय आधार संदिग्ध प्रतीत हों, समिति को उन्हें अपना बचाव तैयार करने के लिए उचित समय देना चाहिए था, विशेष रूप से तब जब एक वकील के माध्यम से प्रतिनिधित्व करने के उनके अनुरोध को पहले ही अस्वीकार कर दिया गया था। यह सारी अनुचित चिंता ही थी जिसके कारण समिति द्वारा की गई जांच की कार्यवाही को छोटा कर दिया गया था और प्रक्रिया की निष्पक्षता को नुकसान पहुंचा था।

23] 7 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

72. उपरोक्त कारणों से, प्रक्रिया और उसके परिणाम पर सवाल उठाने के लिए अपीलार्थी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह महत्वपूर्ण है।

उचित परिणाम। इस मामले में यौन उत्पीड़न के पीड़ितों के प्रति निष्पक्ष होने की समिति की चिंता ने उन्हें और अधिक परेशान कर दिया है हानि पहुँचाते हैं।

73. अतः इस न्यायालय की राय है कि कार्यवाही

मई, 2009 के महीने से समिति द्वारा संचालित, संबंधित नियमों में निर्धारित "जहां तक व्यावहारिक हो सके" मानदंड से कम था। जांच करने का विवेकाधिकार समिति में निहित है

प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों की अवहेलना करते हुए अनुचित तरीके से प्रयोग किया गया है। इसके परिणामस्वरूप, अपीलार्थी प्राधिकरण द्वारा विधिवत समर्थित अपीलार्थी की सेवाओं को समाप्त करने के निर्वाचन आयोग द्वारा लिए गए निर्णय को बरकरार रखने वाले विवादित निर्णय को कायम नहीं रखा जा सकता है और तदनुसार इसे रद्द कर दिया जाता है और निम्नलिखित निर्देशों के साथ अलग कर दिया जाता है:

(i) मामले को 5 मई 2009 को जांच की कार्यवाही शुरू करने के लिए शिकायत समिति को वापस भेज दिया गया है।

((ii)) समिति को पर्याप्त अवसर प्रदान करेगी।

अपना बचाव करने के लिए अपीलार्थी।

((ग)) अपीलार्थी किसी भी स्थगन की मांग नहीं करेगा।

कार्यवाही।

((iv)) समिति द्वारा एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी।

उचित आदेशों के लिए अनुशासनात्मक प्राधिकरण।

(v) लंबे समय के बीतने को ध्यान में रखते हुए, उत्तरदाताओं को समिति द्वारा निर्धारित सुनवाई की पहली तारीख से तीन महीने के भीतर पूरी प्रक्रिया को पूरा करने का निर्देश दिया जाता है।

((vi)) समिति द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया और

अनुशासनिक प्राधिकरण प्राकृतिक नियमों के सिद्धांतों द्वारा निर्देशित होगा।

न्याया।

ऑरिलियानो फर्नांडीस बनाम। गोवा राज्य और अन्य [हिमा कोहली, जे.]

(vii) लागू किए गए नियम वैसे ही होंगे जैसे संबंधित मामलों में लागू थे।

समय का बिंदु।

(viii) समिति और अनुशासनात्मक प्राधिकरण द्वारा लिया गया निर्णय विशुद्ध रूप से गुण-दोष और कानून के अनुसार होगा।

(ix) अपीलार्थी तत्काल दावा करने का हकदार नहीं होगा। जाँच पूरी होने तक बहाली या मजदूरी वापस करना और

निर्णय अनुशासनिक प्राधिकरण द्वारा लिया जाता है।

एन. एपिलॉग

74. जिस तरह हम पी. ओ. एस. एच. अधिनियम के लागू होने के एक दशक का जश्न मना रहे हैं, उसी तरह यह समय पीछे मुड़कर देखने और जनादेश के तरीके का जायजा लेने का है

गलत तरीके से तैयार समिति के आधे संचालन के लिए प्रतिकूल बेकड इन्क्वायरी जो गंभीर परिणामों की ओर ले जा सकती है, अर्थात्, अपराधी कर्मचारी पर बड़े दंड का अधिरोपण, समाप्ति के बिंदु तक

सेवा से।

हाल ही में एक राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्र द्वारा स्पष्ट कमी को सामने लाया गया है जिसने देश में 30 राष्ट्रीय खेल महासंघों का एक सर्वेक्षण किया और प्रकाशित किया है और बताया है कि उनमें से 16 ने आज तक आईसीसी का गठन नहीं किया है। जहाँ आई. सी. सी. पाया गया है, वहाँ उनके पास सदस्यों की निर्धारित संख्या नहीं है या अनिवार्य बाहरी सदस्य की कमी है। यह वास्तव में एक खेदजनक स्थिति है और सभी राज्य अधिकारियों, सार्वजनिक प्राधिकरणों, निजी उपक्रमों, संगठनों और संस्थानों पर खराब प्रभाव डालती है जो पी. ओ. एस. एच. अधिनियम को अक्षरशः लागू करने के लिए कर्तव्यबद्ध हैं। इस तरह का शिकार होना खेदजनक कृत्य न केवल एक महिला के आत्मसम्मान को कम करता है, बल्कि यह उसके भावनात्मक, मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर भी असर डालता है। अक्सर यह देखा जाता है कि जब महिलाओं को कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है, तो वे इस तरह के दुर्व्यवहार की रिपोर्ट करने से हिचकती हैं। उनमें से कई अपनी नौकरी भी छोड़ देते हैं। रिपोर्ट करने के लिए इस अनिच्छा का एक कारण यह है कि एक [2023] 7 एस. सी. आर. है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

उनके निवारण के लिए अधिनियम के तहत किससे संपर्क करना है, इस बारे में अनिश्चितता

शिकायतें। दूसरा प्रक्रिया और उसके परिणाम में विश्वास की कमी है। इस सामाजिक बीमारी को अधिनियम के मजबूत और कुशल कार्यान्वयन के माध्यम से तत्काल सुधार की आवश्यकता है। इसे प्राप्त करने के लिए, शिकायतकर्ता पीड़ित को अधिनियम के महत्व और कार्यप्रणाली के बारे में शिक्षित करना अनिवार्य है। उन्हें इस बात से अवगत कराया जाना चाहिए कि शिकायत कैसे दर्ज की जा सकती है, शिकायत को संसाधित करने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाएगी, जिस उद्देश्यपूर्ण तरीके से आई. सी. सी./एल. सी./आई. सी. से कानून के तहत काम करने की उम्मीद की जाती है, उसके परिणामों की प्रकृति जिसके लिए अपराधी कर्मचारी से मुलाकात की जा सकती है।

यदि शिकायत सही पाई जाती है, तो झूठी या दुर्भावनापूर्ण शिकायत दर्ज करने का परिणाम और उपचार जो किसी व्यक्ति के लिए उपलब्ध हो सकते हैं।

यदि शिकायतकर्ता आई. सी. सी./एल. सी./आई. सी. आदि की रिपोर्ट से असंतुष्ट है।

76. यह अधिनियम चाहे कितना भी हितकारी क्यों न हो, यह कार्यस्थल पर महिलाओं को गरिमा और सम्मान प्रदान करने में कभी सफल नहीं होगा। जब तक प्रवर्तन व्यवस्था का कड़ाई से पालन नहीं किया जाता है और सभी राज्य और गैर-राज्य अभिनेताओं द्वारा एक सक्रिय दृष्टिकोण नहीं है। अगर काम का माहौल महिला कर्मचारियों की जरूरतों के प्रति प्रतिकूल, असंवेदनशील और अनुत्तरदायी बना रहता है, तो यह अधिनियम खाली रहेगा।

औपचारिकता। यदि अधिकारी/प्रबंधन/नियोक्ता उन्हें एक सुरक्षित कार्यस्थल का आश्वासन नहीं दे सकते हैं, तो वे सम्मानजनक जीवन जीने के लिए अपने घरों से बाहर निकलने से डरेंगे और अपनी प्रतिभा और कौशल का पूरा फायदा उठाएंगे। इसलिए, यह केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के लिए सकारात्मक कार्रवाई करने और यह सुनिश्चित करने का समय है कि पी. ओ. एस. एच. अधिनियम को लागू करने के पीछे परोपकारी उद्देश्य को वास्तविक रूप से प्राप्त किया जाए।

ओ. दिशाएँ

77. पूरे देश में कामकाजी महिलाओं के लिए पी. ओ. एस. एच. अधिनियम के वादे को पूरा करने के लिए, निम्नलिखित निर्देश जारी करना उचित समझा जाता है:

(i) भारत संघ, सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को यह सत्यापित करने के लिए एक समयबद्ध अभ्यास करने का निर्देश दिया जाता है कि क्या

पाँश अधिनियम। (ii) यह सुनिश्चित किया जाएगा कि आई. सी. सी./एल. सी./आई. सी. के गठन और संरचना के बारे में आवश्यक जानकारी, ई-मेल आई. डी. और नामित व्यक्ति (ओं) के संपर्क नंबरों का विवरण, प्रक्रिया ऑरेलियानो फर्नांडीस V.

गोवा राज्य और अन्य [हिमा कोहली, जे.]

(iii) शीर्ष स्तर और राज्य स्तर पर पेशेवरों के सभी सांविधिक निकायों द्वारा इसी तरह की कवायद की जाएगी। विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों, प्रशिक्षण केंद्रों और शैक्षणिक संस्थानों द्वारा और सरकारी और निजी अस्पतालों/नर्सिंग होम द्वारा डॉक्टरों, वकीलों, वास्तुकारों, चार्टर्ड एकाउंटेंटों, लागत लेखाकारों, इंजीनियरों, बैंकरों और अन्य पेशेवरों) को विनियमित करना।

(iv) आई. सी. सी./एल. सी./आई. सी. के सदस्यों को परिचित कराने के लिए अधिकारियों/प्रबंधनों/नियोक्ताओं द्वारा तत्काल और प्रभावी कदम उठाए जाएंगे।

उनके कर्तव्यों और कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की शिकायत प्राप्त होने पर जिस तरह से जांच की जानी चाहिए, उस बिंदु से जब शिकायत प्राप्त होती है, जब तक कि जांच अंततः समाप्त नहीं हो जाती है और रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की जाती है।

(v) अधिकारी/प्रबंधन/नियोक्ता नियमित रूप से अभिविन्यास कार्यक्रम, कार्यशालाएं, सेमिनार और जागरूकता आयोजित करेंगे।

आई. सी. सी./एल. सी./आई. सी. के सदस्यों को कुशल बनाने और शिक्षित करने के लिए कार्यक्रम महिला कर्मचारियों और महिला समूहों को अधिनियम, नियमों और प्रासंगिक विनियमों के प्रावधानों के बारे में जानकारी।

(vi) राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण (एन. ए. एल. एस. ए.) और राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण (एस. एल. एस. ए.) संचालन के लिए मॉड्यूल विकसित करेंगे।

अधिनियम के प्रावधानों के साथ अधिकारियों/प्रबंधनों/नियोक्ताओं, कर्मचारियों और किशोर समूहों को संवेदनशील बनाने के लिए कार्यशालाएं और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करें, जिन्हें उनके वार्षिक कैलेंडर में शामिल किया जाएगा।

(vii) राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी और राज्य न्यायिक अकादमियां अपने वार्षिक कैलेंडर में अभिविन्यास को शामिल करेंगी।

सदस्यों के क्षमता निर्माण के लिए कार्यक्रम, सेमिनार और कार्यशालाएं उच्च न्यायालयों और जिला न्यायालयों में स्थापित आई. सी. सी. एस./एल. सी./आई. सी. और अधिनियम और नियमों के तहत जांच करने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एस. ओ. पी.) का मसौदा तैयार करने के लिए।

(viii) इस निर्णय की एक प्रति सचिवों को भेजी जाएगी।

सभी मंत्रालयों, भारत सरकार जो सभी संबंधित विभागों, सांविधिक प्राधिकरणों द्वारा निर्देशों का कार्यान्वयन सुनिश्चित करेंगे, संबंधित मंत्रालयों के नियंत्रण में संस्थान, संगठन आदि। फैसले की एक प्रति प्रमुख [2023] 7 एस. सी. आर. को भी भेजी जाएगी।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सचिव जो सभी संबंधित विभागों द्वारा इन निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करेंगे। मंत्रालयों, भारत सरकार के सचिवों और प्रत्येक राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के मुख्य सचिवों की जिम्मेदारी होगी कि वे जारी किए गए निर्देशों का कार्यान्वयन सुनिश्चित करें। (ix) भारत के सर्वोच्च न्यायालय की रजिस्ट्री इस निर्णय की एक प्रति निदेशक, राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी, सदस्य सचिव, एन. ए. एल. एस. ए., अध्यक्ष, बार काउंसिल ऑफ इंडिया और सभी उच्च न्यायालयों के महापंजीयकों को भेजेगी। रजिस्ट्री एक प्रति भी प्रेषित करेगी।

जारी किए गए निर्देशों को लागू करने के लिए भारतीय चिकित्सा परिषद, वास्तुकला परिषद, चार्टर्ड एकाउंटेंट संस्थान, कंपनी सचिव संस्थान और भारतीय इंजीनियरिंग परिषद को यह निर्णय दिया गया है।

(X) सदस्य-सचिव, एनएलएसए से अनुरोध है कि वे इस निर्णय की एक प्रति सभी राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरणों के सदस्य सचिवों को प्रेषित करें। इसी तरह, राज्य उच्च न्यायालयों के महापंजीयक इस निर्णय की एक प्रति राज्य न्यायिक अकादमियों के निदेशकों और उनके प्रधान जिला न्यायाधीशों/जिला न्यायाधीशों को प्रेषित करेंगे।

संबंधित राज्य।

(xi) अध्यक्ष, भारतीय विधिज्ञ परिषद और ऊपर उप-पैरा (ix) में उल्लिखित शीर्ष निकाय, बदले में, इस निर्णय की एक प्रति सभी राज्य विधिज्ञ परिषदों और राज्य स्तरीय परिषदों को, जैसा भी मामला हो, प्रेषित करेंगे।

78. भारत संघ और सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को अनुपालन की सूचना देने के लिए आठ सप्ताह के भीतर अपने हलफनामे दाखिल करने का निर्देश दिया गया है। आठ के बाद सूची बनाएँ

सप्ताह। 79. पक्षकारों को अपना खर्च वहन करने के लिए छोड़ते हुए उपरोक्त शर्तों पर अपील की अनुमति दी जाती है। लंबित आवेदन, यदि कोई हों, का निपटारा कर दिया जाएगा।

अपील की अनुमति दी गई

और निर्देश जारी किए गए।

अंकित ज्ञान

(सहायक: महेंद्र यादव, एलसीआरए)